



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 553]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 22, 2003/आषाढ़ 1, 1926

No. 553]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 22, 2004/ASADHA 1, 1926

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जून, 2004

का.आ. 711(अ).—सभी राज्य सरकारों को देश में दत्तक-ग्रहण सम्बन्धी दिशा-निर्देश पहली बार दिनांक 14-9-1994 के पत्र सं. 1-4/98-कारा के तहत परिचालित किए गए थे। बाद में, समय-समय पर आवासीय गृहों के लाइसेंस, राज्य दत्तक इकाइयों की स्थापना, राज्य सलाहकार बोर्डों और दत्तक-ग्रहण एजेंसियों के क्रियाकलापों आदि से संबंधित मामलों पर राज्य सरकारों को परिपत्र जारी किए गए हैं। दत्तक-ग्रहण एजेंसियों को अनुदेश भी जारी किए गए हैं ताकि देशभर में समान दत्तक-ग्रहण प्रक्रियाएं अपनाई जाएं।

देश में दत्तक-ग्रहण को विनियमित करने के लिए संशोधित दिशा-निर्देशों के एक सेट की जरूरत को महसूस किया गया है ताकि देशभर में दत्तक-ग्रहण के लिए समान प्रक्रियाओं और मानदण्डों को सुनिश्चित कर लिया जाए, इन नए दिशा-निर्देशों में दत्तक-ग्रहण, शुल्क दत्तकग्राही माता-पिता के लिए आयु मापदण्ड, गृह-अध्ययन आदि शामिल हैं। आशा है कि इन दिशा-निर्देशों से परित्यक्त, बेसहारा अथवा अनाथ बच्चों के देश में वे दत्तक-ग्रहण करने में सुविधा होगी ताकि वे घर जैसे स्नेह और देखरेख वाले माहौल में विकसित होने का अवसर प्राप्त कर सकें जो प्रत्येक बच्चे का अधिकार है।

[सं. 18-8/2003-सीडब्ल्यू]

श्रीमती राजवंत संधू, संयुक्त सचिव

देश में दत्तक-ग्रहण के लिए दिशा-निर्देश-2004

विषय-वस्तु

अध्याय-1

प्रस्तावना एवं प्रक्रियाएं

अध्याय-2

राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की भूमिका

अध्याय - 1

प्रस्तावना एवं प्रक्रियाएं

भारत सरकार ने संवैधानिक अधिदेश के अनुसरण में राष्ट्रीय बाल कल्याण नीति तैयार की है। संक्षेप में यह नीति निम्नलिखित पर बल देती है:

'राष्ट्र के बच्चे अत्यन्त महत्वपूर्ण संपत्ति हैं। उनका पालन-पोषण और उनकी चिंता हमारा दायित्व है। बच्चों के कार्यक्रमों को मानव संसाधन विकास के लिए हमारी राष्ट्रीय योजनाओं में प्रमुख स्थान मिलेगा ताकि हमारे बच्चे दृष्ट-पुष्ट नागरिक, शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से फुरतीले, नैतिक रूप से स्वस्थ हों तथा समाज के लिए आवश्यक कौशलों और प्रेरणाओं से सम्पन्न होकर विकसित हों। विकसित होने की अवधि के दौरान सभी बच्चों को विकास के लिए समान अवसर प्रदान करना हमारा लक्ष्य होना चाहिए क्योंकि इससे असमानता को कम करने और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने संबंधी हमारे बड़े उद्देश्य की पूर्ति होगी।'

उपर्युक्त अधिदेश के अनुसरण में, भारत सरकार ने बच्चों की उन्नति और उनका विकास सुनिश्चित करने के लिए अनेक कार्यक्रम तैयार किए हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार को अन्य के साथ-साथ कठिन परिस्थितियों में पड़े बच्चों के कल्याण का कार्य सौंपा गया है। दत्तक ग्रहण के माध्यम से ऐसे बच्चों का पुनर्वास मंत्रालय की बच्चों से संबंधित नीतियों का एक प्रमुख फलक है। यह नीति इस तथ्य को ध्यान में रखती है कि किसी बच्चे का पूर्ण और दुरुस्त विकास केवल पैतृक प्रेम और मार्गदर्शन के वातावरण में संभव है। यह नीति परिवार को उस केंद्रीय आधार के रूप में मानती है जिसके चारों ओर किसी बच्चे के मानसिक और शारीरिक विकास को विकसित होने के लिए पूरा अवसर दिया जाता है।

1984 के लक्ष्मी कांत पांडेय बनाम भारत संघ मामले में भारत के उच्चतम न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय के अनुसरण में, केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन एजेंसी की स्थापना मंत्रालय द्वारा की गई और उसके बाद भारतीय बच्चों के दत्तक-ग्रहण के लिए संशोधित दिशा-निर्देश देश से बाहर दत्तक-ग्रहणों को विनियमित और मानीटरिंग

करने के लिए नियमों के एक ढांचे की व्यवस्था करने हेतु 1995 में संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए गए। ये दिशा-निर्देश अब पूरे देश में लागू हैं और वे देश से बाहर दत्तक ग्रहणों के मामलों में कार्रवाई करने के लिए एक-समान तंत्र की व्यवस्था करते हैं। हाल ही में मंत्रालय देश के अंदर दत्तक ग्रहणों की मानटरिंग करने और कार्रवाई करने के लिए दिशा-निर्देशों के इसी प्रकार के ढांचे की व्यवस्था करने की आवश्यकता के बारे में सोच रहा है। अपने उपर्युक्त निर्णय में उच्चतम न्यायालय तथा 1989 में संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा अपनाई गई संयुक्त राष्ट्र और घोषणा देश से बाहर दत्तक-ग्रहण संबंधी हेग कन्वेंशन 1993 दोनों में निर्धारित है कि बिना परिवार वाले बच्चे के सर्वोत्तम हित की पूर्ति इसे अपने स्वयं के सामाजिक-आर्थिक परिवेश में रखे जाने का अवसर प्रदान करने के द्वारा होती है। अतः प्रत्येक बच्चे का यह अधिकार है कि उसे देश के भीतर उसके अपने स्वयं के राष्ट्रीय और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से संबंधित परिवार में रखे जाने पर विचार किया जाए। अतः देश से बाहर दत्तक-ग्रहण को एक विकल्प के रूप में देखा जाता है जिस पर तभी विचार किया जाना है जब उपर्युक्त संभव नहीं हो। इसे देश के बाहर दत्तक ग्रहणों को विनियमित करने वाले दिशा-निर्देशों में भी निर्धारित किया गया है।

देश के अंदर दत्तक-ग्रहण का महत्व स्वयं में स्पष्ट है। यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि पूरे देश में देश के अंदर दत्तक-ग्रहण को सक्रियतापूर्वक प्रोत्साहित और प्रचारित किया जाए, परन्तु इसके साथ ही इस उद्देश्य के लिए एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया तैयार की जाए और उसका अनुसरण किया जाए। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार ने अब ऐसी प्रक्रिया के लिए सामान्य दिशा-निर्देश जारी करने का निर्णय किया है जिसे हिंदू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 (एच ए एम ए), किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 (जे जे एक्ट) के अंतर्गत दत्तक ग्रहण याचिकाओं और साथ ही संरक्षण और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 (जी ए डब्ल्यू ए) के अंतर्गत संरक्षता याचिकाओं को दायर करने से पूर्व दत्तक-ग्रहण गृहों/संस्थाओं द्वारा अपनाए जाने की आवश्यकता है। ये दिशा-निर्देश मौजूदा अधिनियमों और कानूनों के उपबंधों को प्रभावित नहीं करते हैं परन्तु दत्तक ग्रहण संबंधी मामलों पर उन्हें उपर्युक्त अधिनियमों के अंतर्गत सक्षम प्राधिकरणों/न्यायालयों के समक्ष वास्तविक रूप से लाए जाने से पूर्व कार्रवाई करने के लिए प्रक्रिया की व्यवस्था करने का कार्य करते हैं। ये दिशा-निर्देश यह भी सुनिश्चित करते हैं कि बालक के सर्वोत्तम हितों की रक्षा की जाए और सभी दत्तक ग्रहणों को केवल लाइसेंस प्राप्त गृहों/संस्थाओं के माध्यम से प्रक्रियाबद्ध किया जाए।

केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण सभी दत्तक-ग्रहण मामलों पर विचार करने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का नोडल निकाय है। भारत सरकार सभी पहलुओं पर उचित ध्यान देने और इस क्षेत्र में विशेषज्ञों से परामर्श करने के पश्चात एतद्वारा देश में दत्तक-ग्रहण के लिए दिशा-निर्देश जारी करती है जो तत्काल रूप से प्रभाव में आएंगे और इस मंत्रालय के दिनांक 14.09.1998 के पूर्ववर्ती परिपत्र संख्या 1-4/98 (कारा) का स्थान लेंगे। भारत सरकार का सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, इन दिशा-निर्देशों में अपने विवेक से ऐसे संशोधन, परिवर्धन, विलोपन या परिवर्तन करने का अधिकार स्वयं में संरक्षित रखेगा जिन्हें समय-समय पर आवश्यक समझा जाए।

लक्ष्य और उद्देश्य:

देश में दत्तक-ग्रहण संबंधी दिशा-निर्देशों का उद्देश्य है:

- देश में दत्तक-ग्रहण के लिए देश भर में एक सामान्य प्रक्रिया को विनियमित करना और आसान बनाना;
- देश के अंदर निराश्रित और अनाथ बच्चों के दत्तक-ग्रहण को बढ़ावा देना।

1.1 दत्तक-ग्रहण गृह

1.1.1 देश में दत्तक-ग्रहण के लिए लाइसेंस प्राप्त दत्तक-ग्रहण स्थापन एजेंसियों की भूमिका एवं कार्य

- (1) देश में दत्तक-ग्रहण के लिए लाइसेंस प्राप्त इस प्रकार की सभी एजेंसियों को सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत किया जाएगा। वे राज्य सरकार/केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर देश में दत्तक-ग्रहण को विनियमित करने के लिए निर्धारित किसी दिशा-निर्देश या नियम का पालन करेंगी। अतः वे बाल देखरेख गृहों को चलाने तथा देश की भीतर दत्तक-ग्रहण में बच्चों को रखने तथा मान्यता/अनुमति के लिए राज्य सरकार से लाइसेंस प्राप्त करेंगी और उन्हें लाइसेंस प्राप्त दत्तक ग्रहण स्थापन एजेंसियों के नाम से जाना जाएगा। दत्तक-ग्रहण गृहों, जिन्हें भारत सरकार द्वारा देश के बाहर दत्तक-ग्रहण के लिए मान्यता तथा जिम्मेदारी भी दी गई है, मान्यता प्राप्त भारतीय स्थापन एजेंसियां कहा जाएगा।

- (2) देश में दत्तक-ग्रहण के लिए लाइसेंस प्राप्त दत्तक-ग्रहण स्थापन एजेंसियों द्वारा सभी बच्चों की प्रविष्टि प्रवेश रजिस्टर में संलग्नक - 1 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में की जाएगी ।
- (3) देश में दत्तक-ग्रहण के लिए लाइसेंस प्राप्त दत्तक-ग्रहण स्थापन एजेंसियां निकटतम स्थित दत्तक-ग्रहण समन्वय एजेंसी की सदस्य होंगी ।
- (4) वे अपने पास पंजीकृत प्रत्याशित दत्तक माता-पिता (माता-पिताओं) के रूप में भारतीय युगलों/व्यक्तियों की एक अलग सूची रखेगी ।
- (5) देश में दत्तक-ग्रहण के लिए लाइसेंस प्राप्त सभी दत्तक-ग्रहण स्थापन एजेंसियों के पास बाल देखभाल सुविधाओं का उंचा स्तर होना चाहिए और उन्हें संलग्नक-4 में दिए गए प्रमुख मानदंडों के अनुसार बाल देखरेख में निर्धारित एवं पर्याप्त मानकों का अनुपालन करना चाहिए । 3 और 6 वर्ष के बीच की आयु के बच्चों के लिए उचित मनोरंजनात्मक और स्कूल पूर्व शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए ।
- (6) देश में दत्तक-ग्रहण के लिए लाइसेंस प्राप्त सभी दत्तक-ग्रहण स्थापन एजेंसियों के लिए अनिवार्य है कि उनके पास अर्हताप्राप्त कर्मचारी हों । 10 बच्चों वाले गृह में निम्नलिखित कर्मचारी होने चाहिए:

1. अधीक्षक - 1
2. नर्स एवं पर्यवेक्षक - 1
3. पूर्णकालिक या अंशकालिक डाक्टर अधिमानतः बाल चिकित्सक - 1
4. सामाजिक कार्यकर्ता - 1
5. आया - 10 बच्चों के लिए 4
6. लेखा एवं प्रशासनिक कर्मचारी - 1
7. चौकीदार - 1

उपर्युक्त स्टाफ ढांचा संस्तुत है और यह बच्चों की संख्या और गृह के आकार के अनुपात में अलग-अलग हो सकता है । व्यवसायिक

कर्मचारियों जैसे नर्सों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के पास संबद्ध अर्हताएं जैसे क्रमशः नर्सिंग में डिग्री/डिप्लोमा तथा एम एस डब्ल्यू/बी एस डब्ल्यू ।

- (7) देश में दत्तक-ग्रहण के लिए लाइसेंस प्राप्त प्रत्येक दत्तक ग्रहण स्थापन एजेंसी का नैतिक एवं कानूनी दायित्व है कि वह कानून की परिधि के अंतर्गत तथा बच्चे के सर्वोत्तम हित में कार्य करें । एक गृह किसी अनाथ या निराश्रित को प्रवेश देते समय उस बच्चे को एक नाम देगा, बच्चे के पहचान के निशानों को दर्ज करेगा, बच्चे की लंबाई और वजन को दर्ज करेगा, बच्चे की चिकित्सा जांच करेगा, और बच्चे के फोटोग्राफ खिंचवाएगा । सभी नए आगंतुकों के मामले में स्थानीय प्राधिकरण को 24 घंटे के अंदर सूचित किया जाएगा और किसी त्यागे हुए बच्चे को प्रवेश देने के मामले में वह गृह नजदीकी थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाएगा तथा स्थानीय प्राधिकरण और बाल कल्याण समिति को 24 घंटे के अंदर सूचित करेगा ।
- (8) राज्य सरकार के राज्य दत्तक-ग्रहण प्रकोष्ठ को उपलब्ध बच्चों की संख्या के संबंध में एक मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी । किसी बच्चे की मौत की सूचना भी ब्यौरा देते हुए तत्काल स्थानीय प्राधिकरण, दत्तक-ग्रहण समन्वय एजेंसी तथा राज्य दत्तक-ग्रहण प्रकोष्ठ को 48 घंटे के अंदर दी जाएगी । देश में दत्तक-ग्रहण के लिए लाइसेंस प्राप्त दत्तक-ग्रहण स्थापन एजेंसी के पदाधिकारी द्वारा प्रति-हस्ताक्षरित फोटोग्राफ के साथ मृत्यु प्रमाण-पत्र को व्यक्तिगत रिकार्ड फाइल काउंटर में रखा जाएगा । देश में दत्तक-ग्रहण लाइसेंस प्राप्त प्रत्येक दत्तक ग्रहण स्थापन एजेंसी बच्चे के पूरे पूर्ववृत्त के साथ प्रत्येक बच्चे के लिए एक अलग फाइल रखेगी । प्रत्येक बच्चे की एक बाल अध्ययन रिपोर्ट हो जिसे प्रत्याशित दत्तक माता-पिता को दिखाया जाएगा । इस प्रकार की रिपोर्ट का प्रपत्र संलग्नक-5 में दिया गया है ।
- (9) सभी पंजीकृत प्रत्याशित दत्तक माता या पिता (माता-पिता) परामर्श सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं जिन्हें देश में दत्तक-ग्रहण लाइसेंस प्राप्त दत्तक-ग्रहण स्थापन एजेंसी द्वारा निःशुल्क दिया जाना है । उन्हें विस्तारपूर्वक परामर्श दिया जाए और उन्हें एक बार बच्चे को गोद ले लिए जाने पर कानूनी बाध्याओं, स्वयं बच्चे के अधिकारों, उन विभिन्न

अधिनियमों जिनके अंतर्गत किसी बच्चे को परिवार में रखा जा सकता है, जन्म प्रमाण-पत्र प्राप्त करने आदि की प्रक्रियाओं की जानकारी दी जाए ।

- (10) देश में दत्तक ग्रहण के लिए लाइसेंस प्राप्त दत्तक-ग्रहण स्थापन एजेंसियां अपने पास उपलब्ध बच्चों की सूची प्रासंगिक सूचना के साथ दत्तक-ग्रहण समन्वय एजेंसी और राज्य दत्तक-ग्रहण प्रकोष्ठ को उनके पास पंजीकृत उपयुक्त दत्तक माता या पिता (माता-पिता) की तलाश करने के कार्य को आसान बनाने के लिए प्रत्येक माह भेजेंगी ।
- (11) उचित न्यायालय में किसी बच्चे के दत्तक ग्रहण या स्थापन के लिए आवेदन दायर करते समय देश में दत्तक ग्रहण लाइसेंस प्राप्त दत्तक ग्रहण स्थापन एजेंसी भी सह-प्रतिवादी होगी । बच्चा न्यायालय आदेश के द्वारा अंतिम स्थापना किए जाने तक देश में दत्तक ग्रहण लाइसेंस प्राप्त दत्तक ग्रहण स्थापन एजेंसी के अधिकार में होगा । अतः माता या पिता (माता-पिता) किसी याचिका को सीधे दायर नहीं कर सकते और जैविक अविवाहित माता का खुलासा माता या पिता (माता-पिता) को याचिका के एक अंग के रूप में नहीं किया जा सकता । यदि इन उपबंधों का उल्लंघन ध्यान में आए तो राज्य सरकार द्वारा देश में दत्तक-ग्रहण के लिए लाइसेंस प्राप्त दत्तक-ग्रहण स्थापना एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी । अभ्यर्पण दस्तावेज को गोपनीय माना जाए और केवल न्यायालय को प्रस्तुत किया जाए । देश में दत्तक-ग्रहण के लिए लाइसेंस प्राप्त दत्तक-ग्रहण स्थापन एजेंसी को सुनिश्चित करना चाहिए कि दत्तक-ग्रहण संबंधी याचिकाएं शीघ्र ही न्यायालय में दायर की जाएं और शीघ्र आदेश प्राप्त करने के लिए न्यायालय को सभी प्रकार का सहयोग दिया जाए ।
- (12) देश में दत्तक-ग्रहण के लिए लाइसेंस प्राप्त दत्तक-ग्रहण स्थापन एजेंसी दत्तक-ग्रहण समन्वय एजेंसी और राज्य दत्तक ग्रहण प्रकोष्ठ को संलग्नक-2 के अनुसार एक मासिक रिपोर्ट भेजेगी ।

1.1.2 देश में दत्तक-ग्रहण के लिए लाइसेंस प्राप्त दत्तक-ग्रहण स्थापन एजेंसी को बच्चे को प्रवेश देने का तरीका

देश में दत्तक-ग्रहण के लिए लाइसेंस प्राप्त दत्तक-ग्रहण स्थापन एजेंसी में दो तरीकों से किसी बच्चे को प्रवेश दिया जा सकता है:

- (1) जैविक माता या पिता (माता-पिता)/अविवाहित माता द्वारा सीधे अभ्यर्पण ।
- (2) देश में दत्तक-ग्रहण के लिए लाइसेंस प्राप्त दत्तक-ग्रहण स्थापन एजेंसी में या अन्यत्र त्यागा हुआ या किसी तीसरे पक्ष या पुलिस द्वारा लाया गया या बाल कल्याण समिति द्वारा भेजा गया बच्चा ।

1.1.3 जैविक पालक (माता-पिता) द्वारा किसी बच्चे को सौंपना

- (1) किसी अभ्यर्पित बच्चे के मामले में देश में दत्तक-ग्रहण के लिए लाइसेंस प्राप्त संबंधित दत्तक-ग्रहण स्थापन एजेंसी द्वारा जैविक माता या पिता (माता-पिता) से उनके निर्णय के प्रभाव तथा बच्चे की देखरेख और भरण-पोषण के लिए उपलब्ध विकल्पों के बारे में परामर्श किया जाए और विधिवत सूचित किया जाए । देश में दत्तक-ग्रहण के लिए लाइसेंस प्राप्त दत्तक-ग्रहण स्थापन एजेंसी सीधे या एजेंटों के माध्यम से वित्तीय या अन्य प्रोत्साहनों से अपने बच्चे को अभ्यर्पित करने के लिए जैविक माता या पिता (माता-पिता) से आग्रह करने का प्रयास नहीं करेगी ।
- (2) अभ्यर्पण दस्तावेज जैविक माता या पिता (माता-पिता) द्वारा किसी के दबाव, भुगतान या किसी प्रकार के मुआवजे के बिना वास्तविक रूप से निष्पादित किया जाएगा ।
- (3) देश में दत्तक-ग्रहण के लिए लाइसेंस प्राप्त दत्तक-ग्रहण स्थापन एजेंसी द्वारा माता या पिता (माता-पिता) को अभ्यर्पण की तारीख से 60 दिनों के अंदर बच्चे को वापस लेने के उनके अधिकार की जानकारी दी जाए । उन्हें यह जानकारी दी जानी चाहिए कि 60 दिनों की अवधि के बाद अभ्यर्पण दस्तावेज अपरिवर्तनीय हो जाएगा और बालक को दत्तक-ग्रहण

के लिए मुक्त समझा जाएगा तथा देश में दत्तक-ग्रहण के लिए लाइसेंस प्राप्त दत्तक-ग्रहण स्थापन एजेंसी बच्चे को दत्तक-ग्रहण में या संरक्षकता में रखने के लिए स्वतंत्र होगी ।

- (4) अभ्यर्पण दस्तावेज को दो जिम्मेवार गवाहों की उपस्थिति में स्टाम्प-पत्र में निष्पादित किया जाएगा, जिनमें से एक जिम्मेवार व्यक्ति होगा जो संगठन का कर्मचारी नहीं होगा । दस्तावेजों पर एक नोटरी/शपथ आयुक्त द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे । देश में दत्तक-ग्रहण के लिए लाइसेंस प्राप्त दत्तक-ग्रहण स्थापन एजेंसी को इन गवाहों को यदि आवश्यकता पड़ जाए तो प्रस्तुत करने में समर्थ होना चाहिए । अभ्यर्पण दस्तावेज की प्रमाणिकता के लिए दायित्व देश में दत्तक-ग्रहण के लिए लाइसेंस प्राप्त दत्तक-ग्रहण स्थापन एजेंसी का होगा । बच्चे को अभ्यर्पित करने वाले किसी नाबालिग के मामले में माता या पिता (माता-पिता)/रिश्तेदार (रिश्तेदारों) के कम से कम एक हस्ताक्षर उस की उपस्थिति में प्राप्त किए जाएं । राज्य सरकार को सभी अभ्यर्पण दस्तावेजों की जांच करने का अधिकार होगा तथा इनकी प्रतियां दत्तक-ग्रहण प्रकोष्ठ/विभाग को भेजी जानी हैं । इस अभ्यर्पण प्रक्रिया के दौरान देश में दत्तक-ग्रहण के लिए लाइसेंस प्राप्त दत्तक-ग्रहण स्थापन एजेंसी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि:

- (क) यदि वैवाहिक अवस्था में पैदा हुए बच्चे को अभ्यर्पित किया जाता है, तो माता-पिता दोनों अभ्यर्पण दस्तावेज पर हस्ताक्षर करें और यदि माता या पिता (माता-पिता) की मृत्यु हो गई हो, तो मृत्यु का प्रमाण प्रस्तुत किया जाए । जहां मृत्यु प्रमाणपत्र उपलब्ध न हो वहां स्थानीय सरपंच/पंचायत/सरकारी प्राधिकरण से प्रमाणपत्र पर्याप्त होना चाहिए ।
- (ख) वैवाहिक अवस्था के बिना पैदा हुए बच्चे के मामले में कोई अन्य नहीं बल्कि स्वयं माता बच्चे का अभ्यर्पण कर सकती है । यदि वह अवयस्क हो तो उसके साथ आए रिश्तेदार के हस्ताक्षर अभ्यर्पण दस्तावेज पर लिए जाएंगे ।

- (ग) यदि जैविक माता या पिता (माता-पिता) से अन्य व्यक्ति द्वारा अभ्यर्पण प्रभाव में लाया गया हो तो उसी प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा जो किशोर न्याय अधिनियम, 2000 के अंतर्गत किसी परित्यक्त बच्चे के लिए किया जाता है क्योंकि बच्चे को त्यागा हुआ समझा जाएगा ।
- (घ) जब कोई बच्चा कि विवाहित युगल से जन्म लेता है परंतु माता-पिता में से किसी एक के द्वारा अभ्यर्पित किया जाता है और दूसरे का अता-पता मालूम नहीं होता है तो उसी प्रक्रिया का अनुपालन किया जाता है जो किसी परित्यक्त बच्चे के लिए किया जाता है ।
- (ङ) यदि अभ्यर्पण के दस्तावेज को राज्य सरकार द्वारा अवैध/अपूर्ण समझा जाता है तो यह संबंधित एजेंसी को वही प्रक्रिया का अनुसरण करने का निर्देश देती है जैसा कि किशोर न्याय अधिनियम, 2000 के अंतर्गत है । तथापि, इस प्रकार के किसी निर्देश की सूचना एजेंसी को अभ्यर्पण दस्तावेजों की प्रति प्राप्त करने के 15 दिनों के अंदर दी जानी चाहिए ।

1.1.4 परित्यक्त बालक

(1) परित्यक्त बच्चे से संबंधित प्रक्रिया किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 द्वारा निर्धारित की गई है । जबकि बाल कल्याण समिति बच्चों की देखरेख, संरक्षण, व्यवहार, विकास और पुनर्वास संबंधी मामलों के निपटान के लिए अंतिम प्राधिकरण है (उक्त अधिनियम की धारा 31.1), किसी बच्चे को निम्नलिखित व्यक्तियों के द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है (उक्त अधिनियम की धारा 32.1):

- (क) कोई पुलिस अधिकारी या विशेष किशोर पुलिस इकाई या पदनामित पुलिस अधिकारी;
- (ख) कोई जन सेवक;
- (ग) चाइल्डलाइन, एक स्वैच्छिक संगठन या किसी अन्य स्वैच्छिक संगठन या एक एजेंसी जैसा कि राज्य सरकार द्वारा मान्यता दी जाए;

- (घ) कोई सामाजिक कार्यकर्ता या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत जनभावना वाला नागरिक; या
- (ङ) स्वयं बालक के द्वारा ।

(2) जहां कहीं देश में दत्तक-ग्रहण के लिए लाइसेंस प्राप्त दत्तक-ग्रहण स्थापन एजेंसी किसी परित्यक्त बच्चे को अपनी देखरेख में प्राप्त करती है तो यह तत्काल संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज करेगी और बाल कल्याण समिति को 24 घंटों के अंदर बच्चे को अपने अधिकार में रखने के लिए अनुमति प्राप्त करने हेतु आवेदन करेगी ।

(3) देश में दत्तक-ग्रहण के लिए लाइसेंस प्राप्त दत्तक-ग्रहण स्थापन एजेंसी परित्यक्त बच्चों के मामले में बाल कल्याण समिति से स्वीकृति की प्रक्रिया को शीघ्रातिशीघ्र प्रारंभ करेगी तथा बाल कल्याण समिति बच्चे को कानूनी रूप से मुक्त करने की घोषणा करने हेतु दो माह की अवधि के अंदर सभी प्रयास करेगी ।

(4) परित्यक्त बच्चों के मामले में किशोर न्याय (बालकोंकी देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 के अंतर्गत यथा-निर्धारित ऐसे बच्चों को दत्तक-ग्रहण के लिए कानूनी रूप से मुक्त घोषित करने हेतु प्रक्रिया लागू होगी । किसी परित्यक्त बच्चे को दत्तक-ग्रहण में केवल तभी दिया जा सकता है जब किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 के अंतर्गत किशोर न्याय अधिनियम, 2000 की धारा 41 (5) (क) के अनुसार बाल कल्याण समिति के कम से कम दो सदस्यों के द्वारा ऐसे आदेश पर हस्ताक्षर होने पर बाल कल्याण समिति ऐसे बच्चे को दत्तक-ग्रहण के लिए कानूनी रूप से मुक्त घोषित कर देती है । धारा 32 के अंतर्गत रिपोर्ट प्राप्त होने पर समिति, या कोई पुलिस अधिकारी या विशेष किशोर पुलिस इकाई या पदनामित पुलिस अधिकारी द्वारा निर्धारित तरीके से जांच की जाती है और समिति स्वयं या किसी व्यक्ति अथवा एजेंसी से प्राप्त रिपोर्ट पर, जैसा कि किशोर न्याय अधिनियम, 2000 की धारा 32 की उप-धारा (1) में उल्लेख किया गया है, किसी सामाजिक कार्यकर्ता या बाल कल्याण अधिकारी द्वारा त्वरित जांच करने के लिए बच्चे को बाल-गृह में भेज दिया जाता है । इस धारा के अंतर्गत जांच को इतनी कम अवधि में पूर्ण करना होगा जो समिति द्वारा निर्धारित की जाएगी ।

(5) जहां कोई बाल कल्याण समिति कार्य नहीं कर रही हो वहां जिला कलेक्टर या इस उद्देश्य के लिए राज्य सरकार द्वारा शक्ति प्रदत्त कोई अन्य प्राधिकारी परित्याग-प्रमाण-पत्र जारी कर सकता है ।

1.1.5 देश में दत्तक-ग्रहण की प्रक्रिया

चरण-1

- प्रत्याशित दत्तक माता या पिता (माता-पिता) को देश से बाहर दत्तक-ग्रहण के लिए मान्यता प्राप्त स्थानीय दत्तक-ग्रहण एजेंसी/देश में दत्तक-ग्रहण के लिए लाइसेंस प्राप्त दत्तक-ग्रहण स्थापन एजेंसी या दत्तक-ग्रहण समन्वय एजेंसी या राज्य दत्तक-ग्रहण प्रकोष्ठ के पास स्वयं को पंजीकृत करना चाहिए ।

चरण-2

- प्रत्याशित दत्तक माता-पिता की गृह अध्ययन रिपोर्ट एजेंसी के सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा तैयार की जाएगी । प्रत्याशित दत्तक माता-पिता के भय और आशंकाओं को कम करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा दत्तक-पूर्व परामर्श बैठकें गृह अध्ययन रिपोर्ट को तैयार करने के दौरान की जाएंगी । किसी युगल की उनसे नहीं जन्मे बालक की माता या पिता बनने की क्षमता का आकलन करना किसी सफल दत्तक-ग्रहण में अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य होता है । इसलिए उनसे असम्बद्ध बालक की देखरेख करने की उनकी क्षमता का आकलन इस गृह अध्ययन और परामर्श के माध्यम से किया जाता है । प्रत्याशित माता या पिता (माता-पिता) की वित्तीय और स्वास्थ्य स्थिति इस गृह अध्ययन रिपोर्ट का हिस्सा होगी ।
- माता या पिता (माता-पिता) द्वारा देश से बाहर दत्तक-ग्रहण संबंधी आवेदनों के मामले में किसी देश से बाहर दत्तक-ग्रहण के लिए मान्यता प्राप्त स्थापन एजेंसी/देश में दत्तक-ग्रहण के लिए लाइसेंस प्राप्त दत्तक-ग्रहण स्थापन एजेंसी में कार्यरत अर्हताप्राप्त सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा तैयार की गई गृह अध्ययन रिपोर्ट उनके साथ लगी होगी । जहां राज्य सरकारों ने इस प्रकार का कार्य अपने पदाधिकारी को सरकारी तौर पर

सौंपा गया हो वहां संबंधित पदाधिकारी द्वारा गृह अध्ययन रिपोर्ट तैयार की जा सकेगी ।

- माता या पिता (माता-पिता) की पालन-पोषण के मानदंडों का पालन किया जाएगा, जैसा कि पैरा 1.1.7 में उल्लेख किया गया है ।
- एजेंसी प्रवेश किए गए बच्चों में से दत्तक-ग्रहण के लिए कानूनी रूप से मुक्त बच्चों में से उपयुक्त हवाला देगी । यदि कोई उपयुक्त बच्चा उपलब्ध न हो तो परिवार को दत्तक-ग्रहण समन्वय एजेंसी को भेजा जाएगा ।

चरण-3

- किसी गृह अध्ययन रिपोर्ट को स्वीकार और अनुमोदित कर लिए जाने के बाद बच्चे को माता या पिता (माता-पिता) को दिखाया जाएगा । एजेंसी माता या पिता (माता-पिता) द्वारा वांछित बच्चे की बैठक के उपयुक्त वर्णन, यदि कोई हो, के बारे में ध्यान रखेगी ।
- बड़े बच्चों (6 वर्ष से अधिक की आयु) के स्थापन के मामले में बच्चे की लिखित तथा मौखिक सहमति प्राप्त की जाएगी ।

चरण-4

- एक बार सफल मेल-मिलाप कर लिया जाता है तो एजेंसी संगत अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक आदेश प्राप्त करने के लिए न्यायालय/किशोर न्याय बोर्ड में याचिका दायर करेगी । उपर्युक्त प्रक्रिया सामान्यतः 6 से 8 सप्ताह में पूर्ण की जाएगी ।

अधिनियम के तहत दत्तक-ग्रहण

हिन्दू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956/संरक्षण और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1980/किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम, 2000 के अंतर्गत बच्चे को माता या पिता (माता-पिता) के साथ कानूनी रूप से रखा जा सकता है । प्रत्याशित माता-पिता को उपलब्ध विभिन्न अधिनियमों और उनमें से प्रत्येक की शाखाओं-प्रशाखाओं के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए । यह निर्णय करना

उन्हीं पर छोड़ दिया जाए कि वे किस अधिनियम के तहत अपनी याचिका दायर करना चाहेंगे बशर्ते कि वे चुने गए अधिनियम के अंतर्गत ऐसा करने के पात्र हों। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, प्रत्याशित माता-पिता को प्रत्येक अधिनियम के अंतर्गत उनके दत्तक-ग्रहण की स्थिति की पूरी जानकारी दी जानी चाहिए।

अनुवर्ती दौरे

एक बार आदेश जारी कर दिया जाता है तो इसके बाद बच्चे के नए परिवेश में व्यवस्थित हो जाने तक सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा नियमित अनुवर्ती दौरे और दत्तक-ग्रहण के बाद के परामर्श होने चाहिए। यह अनुवर्ती कार्य अधिमानतः कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए या न्यायालय/किशोर न्याय बोर्ड द्वारा यथावांछित अवधि के लिए होने चाहिए। अनुवर्ती रिपोर्टों की प्रतियां जिला समाज कल्याण अधिकारी/संबंधित राज्य सरकार विभाग, संबंधित संवीक्षा एजेंसी तथा न्यायालय/किशोर न्याय बोर्ड, जहां से आदेश प्राप्त हुआ हो, भेजी जाएंगी।

1.1.6 दत्तक-ग्रहण लागत

भरण-पोषण व्यय बच्चे के प्रवेश की तारीख से उसके स्थापन-पूर्व पोषण देखरेख में रखे जाने की तारीख तक 50 रुपए प्रतिदिन की दर से 15,000 रुपए से अधिक नहीं होगा। विशेष चिकित्सा देखभाल, अस्पताल में इलाज के लिए रखे जाने के खर्च के लिए वास्तविक बिलों को प्रस्तुत करने पर अधिकतम 9,000 रुपए तक का दावा किया जा सकता है। कानूनी फीस और संवीक्षा फीस किए गए वास्तविक व्यय के आधार पर ली जा सकती है। शिशु गृह स्कीम के अंतर्गत केन्द्र सरकार से सहायता अनुदान प्राप्त कर रहे गैर-सरकारी संगठन तथा सरकारी गृह इस स्कीम के केवल पैरा 5.4 में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार दत्तक माता-पिता से भरण-पोषण तथा कानूनी फीस की मांग कर सकते हैं। देश में दत्तक-ग्रहणों के लिए फीस का ढांचा भी सम्पूर्ण देश के लिए एक-समान आधार स्थापित करने हेतु तैयार किया गया है। (तथापि, निर्धारित फीस दत्तक-ग्रहण आदेश जारी करने वाले न्यायालय द्वारा इस संबंध में दिए गए किसी निर्देश के अधीन होगी)। उपर्युक्त व्यय के अलावा एजेंसी दत्तक माता-पिता

से प्रत्येक मामले में पंजीकरण व्यय के रूप में 200 रुपए तथा गृह अध्ययन रिपोर्ट तैयार करने के लिए 1000 रुपए की मांग कर सकते हैं।

1.1.7 प्रत्याशित दत्तक माता-पिता के लिए मानदंडः

- क) गृह अध्ययन रिपोर्ट में वैवाहिक स्थिति, आयु और बच्चे के भरण-पोषण के लिए उचित आय वाली वित्तीय स्थिति तथा स्पष्ट साफ-सुथरा पुलिस रिकार्ड होना चाहिए।
- ख) 90 वर्ष तथा उससे कम की संयुक्त आयु वाले प्रत्याशित दत्तक माता-पिता के बारे में, जहां माता-पिता ने 45 वर्ष की आयु पार न कर ली हो, भारतीय बच्चे के दत्तक-ग्रहण के लिए विचार किया जा सकता है। गृह अध्ययन रिपोर्ट स्पष्ट रूप से उल्लिखित कारणों से अपवादात्मक मामलों में इन उपबंधों में उपयुक्त रूप से छूट दी जा सकती है। तथापि, प्रत्याशित दत्तक माता या पिता (माता-पिता) की आयु 55 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- ग) चिकित्सा संबंधी समस्याओं वाले विशेष जरूरतमंद बच्चों के मामलों में दत्तक माता या पिता (माता-पिता) की आयु सीमा में संबंधित राज्य सरकार द्वारा छूट दी जा सकती है।
- घ) एकल व्यक्ति भी, जिन्होंने 45 वर्ष की आयु पार नहीं कर ली हो और जो अन्य मानदंडों को पूरा करते हों, गोद ले सकते हैं।
- ङ) प्रत्याशित माता या पिता (माता-पिता) की आय का नियमित स्रोत होना चाहिए और कम से कम 3000 रुपए प्रतिमाह की न्यूनतम औसत आय हो। तथापि, परिसम्पत्तियों और सहायता तंत्र अर्थात् स्वयं का घर आदि को ध्यान में रखते हुए कम आय पर विचार किया जाएगा।
- च) दत्तक माता-पिता के लिए उपर्युक्त सभी मानदंड नीचे दी गई अतिरिक्त अपेक्षाओं के साथ एकल माता-पिताओं पर भी लागू होंगे:

1. आयु : दत्तक एकल माता या पिता की उम्र 30 वर्ष से अधिक और 45 वर्ष से कम होनी चाहिए।
2. आयु भिन्नता : एकल माता या पिता तथा दत्तक बालक के मध्य आयु की भिन्नता 21 वर्ष होनी चाहिए।

परिवार : एकल माता या पिता के पांस अतिरिक्त पारिवारिक सहायता तंत्र होना चाहिए ।

1.1.8 पात्र बच्चों के लिए मानदंड

- बालक दत्तक ग्रहण के लिए कानूनी रूप से मुक्त होना चाहिए ।
- सहोदर भाई-बहनों/जुड़वां/तीन बच्चे आदि को अलग नहीं किया जाना चाहिए ।
- 6 वर्ष से अधिक की आयु के बच्चों की सहमति भी दत्तक-ग्रहण के लिए ली जानी चाहिए ।

1.1.9 गृह अध्ययन रिपोर्ट के लिए प्रक्रिया

देश में दत्तक-ग्रहण के लिए लाइसेंस प्राप्त दत्तक-ग्रहण स्थापन एजेंसी तथा दत्तक-ग्रहण समन्वय एजेंसियां गृह अध्ययन रिपोर्ट तैयार करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण करेंगी:

1. इसे माता या पिता (माता-पिता) के पंजीकरण के बाद ही तैयार किया जाए ।
2. इसे अर्हता प्राप्त किसी सामाजिक कार्यकर्ता या राज्य के पदनामित अधिकारी द्वारा माता-पिता दोनों के अलग-अलग तथा एक साथ साक्षात्कार के पश्चात् तैयार किया जाए ।
3. परिवार के अन्य सदस्यों का भी यदि वे संयुक्त परिवार में रहते हैं तो साक्षात्कार लिया जाए ।
4. माता या पिता (माता-पिता) को मुक्त दत्तक-ग्रहण सहित दत्तक-ग्रहण संबंधी मुद्दों पर परामर्श दिया जाए ।
5. सभी वैवाहिक दस्तावेजों, विवाह प्रमाण-पत्र, आय का प्रमाण आदि की जांच की जाए और उन्हें रिपोर्ट के साथ संलग्न किया जाए ।

1.1.10 रक्षोपाय

देश में दत्तक-ग्रहण में बच्चे का स्थापन करते समय निम्नलिखित रक्षा-उपायों को सुनिश्चित किया जाना चाहिए:

- (क) बालक दत्तक-ग्रहण के लिए कानूनी रूप से मुक्त हो ।
- (ख) दत्तक-ग्रहण के लिए छोड़े गए बच्चे के लिए दो माह की पुनर्विचार अवधि का पालन किया जाना चाहिए ।
- (ग) परित्यक्त बालकों के लिए निर्धारित ढांचे के अनुसार जैविक माता या पिता (माता-पिता) को खोजने के सभी प्रयास किए जाएं ।
- (घ) एजेंसी में पहले से पंजीकृत आवेदकों को प्राथमिकता दी जाए और उन्हें अपने आवेदनों की स्थिति की नियमित रूप से सूचना दी जाए ।
- (ङ) शारीरिक जांच रिपोर्ट के साथ बाल अध्ययन रिपोर्ट पर दत्तक माता-पिता दोनों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएं ।
- (च) माता या पिता (माता-पिता) को संदेह के मामले में बच्चे को अपने स्वयं के डाक्टर से आकलन कराने की सलाह दी जाए ।
- (छ) दत्तक-ग्रहण फीस के लिए रसीद जारी की जाए ।
- (ज) 6 वर्ष से बड़े बच्चों के लिए राज्य सरकार की विशेष स्वीकृत ली जाए ।
- (झ) यदि प्रत्याशित दत्तक माता या पिता (माता-पिता) विकलांगता/स्वास्थ्य समस्या वाले बच्चे को गोद लेने के इच्छुक हों तो इसका उल्लेख करने से संबंधित दस्तावेज प्राप्त किया जाएगा ।
- (ञ) एक अकेले पुरुष के साथ लड़कियों के स्थापन की तथा एक ही लिंग के युगलों के साथ बच्चों के स्थापन की अनुमति नहीं है ।
- (ट) सहोदर भाई-बहनों और जुड़वां आदि को अलग नहीं किया जाना चाहिए । प्रत्याशित दत्तक माता-पिता (माता-पिता) को इसकी जानकारी दी जाए ।
- (ठ) प्रत्याशित दत्तक माता/पिता (माता-पिता) बच्चे को केवल तभी दत्तक-ग्रहण पूर्व पोषण-देखभाल शपथ-पत्र हस्ताक्षर करने पर बच्चे को ले सकते हैं जब मामले को न्यायालय में दायर किया जाता है ।
- (ड) प्रत्याशित दत्तक माता या पिता (माता-पिता) की उम्र, आय आदि के निर्धारित मानदंड पूरा करें ।
- (ढ) इसके अतिरिक्त, एजेंसी को इस बात से स्वयं को संतुष्ट कर लेना चाहिए कि प्रस्तावित दत्तक-ग्रहण बच्चे के सर्वोत्तम हित में है ।

1.1.11 न्यायालय प्रक्रिया

- (1) दत्तक-ग्रहण एजेंसी द्वारा प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ दत्तक-ग्रहण याचिका संबंधित परिवार न्यायालय/जिला-न्यायालय/किशोर न्याय बोर्ड, जैसा भी मामला हो, के समक्ष दायर की जाए।
- (2) न्यायालय/किशोर न्याय बोर्ड उस याचिका को अपने-अपने क्षेत्राधिकार में संवीक्षा एजेंसियों को भेज सकते हैं।

1.1.12 जन्म प्रमाण-पत्र

दत्तक-ग्रहण में दिए जा रहे परित्यक्त बच्चे की जन्मतिथि किशोर न्याय बोर्ड के आदेश में दर्ज की जाएगी। अन्य सभी मामलों में जहां बच्चे को गोद नहीं लिया गया हो अथवा किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत इसका दत्तक-ग्रहण कार्यान्वित नहीं किया गया हो तथा इसकी जन्मतिथि शासकीय तौर पर दर्ज नहीं की गई हो तो संबंधित दत्तक-ग्रहण एजेंसी को अन्य सामग्री के साथ, जिसे दत्तक ग्रहण एजेंसी संगत समझती हो, स्थानीय मजिस्ट्रेट को दत्तक ग्रहण एजेंसी से संबंधित किसी उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा निष्पादित शपथ-पत्र के रूप में आवेदन करना चाहिए। स्थानीय मजिस्ट्रेट तब जन्म प्रमाणपत्र में प्रविष्टि किए जाने वाले ब्यौरे को अनुमोदित करते हुए आदेश पारित करेगा और मजिस्ट्रेट के आदेश के आधार पर उस नगर/टाउन/क्षेत्र के स्थानीय जन्म प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा, जहां वह बच्चा मिला है। इस प्रक्रिया को केवल दत्तक-ग्रहण को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही आरंभ किया जाएगा ताकि उस प्रमाणपत्र में शामिल करने के लिए दत्तक माता-पिता का ब्यौरा उपलब्ध हो सके। यदि बच्चे ने तीन वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, और दत्तक-ग्रहण को अब भी अंतिम रूप नहीं दिया गया हो, तो एजेंसी एक शपथ-पत्र के रूप में न्यायालय को सूचित करने के बाद जन्म प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकती है, यदि इसे आवश्यक समझा जाए:

- (क) कि इसकी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार बालक ने तीन वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है;
- (ख) कि उसके दत्तक ग्रहण को अंतिम रूप नहीं दिया गया है, तथा कुछ समय लगने की संभावना है या पूरी संभावना है कि कभी भी अंतिम रूप नहीं दिया जा सकता;
- (ग) कि शैक्षिक/चिकित्सीय/कानूनी प्रयोजनों या किसी अन्य उचित प्रयोजन, जिसे विनिर्दिष्ट किया जाए, के लिए एक प्रमाणपत्र अपेक्षित है; तथा
- (घ) कि व्यक्ति स्थानीय बच्चे के माता-पिता के रूप में उस समय तक स्थान लेगा/लेंगे (यह व्यक्ति/ये व्यक्ति एजेंसी से संबंधित उत्तरदायी व्यक्ति होगा/होंगे), जब तक कि वह वयस्कता प्राप्त नहीं कर लेता/लेती या गोद नहीं लिया जाता/ले ली जाती, जो भी पहले हो। ऐसे मामलों में दत्तक-ग्रहण के बाद बच्चे तथा दत्तक माता या पिता (माता-पिता) के नाम/नामों में परिवर्तन की व्यवस्था करने के लिए उस न्यायालय, जिसने मूल जन्म प्रमाणपत्र जारी करने के लिए आदेश पारित किया था, से उस आशय का आदेश प्राप्त करने के बाद दूसरा जन्म प्रमाणपत्र जारी किया जा सकता है।

1.1.13 वे रिकार्ड और दस्तावेज जिन्हें देश में दत्तक ग्रहण लाइसेंस प्राप्त दत्तक ग्रहण स्थापन एजेंसी द्वारा रखा जाना है

देश में दत्तक-ग्रहण के लिए लाइसेंस प्राप्त प्रत्येक दत्तक-ग्रहण स्थापन एजेंसी निम्नलिखित रिकार्ड और दस्तावेज कायम रखेगी:

- (1) प्रवेश रजिस्टर - बच्चे से संबंधित सभी ब्यौरे जिसमें उसके आगमन, जन्म-तिथि, बच्चे को कानूनी रूप से दत्तक-ग्रहण योग्य बनाने संबंधी प्रक्रिया, दत्तक-ग्रहण पूर्व पोषण देखभाल, दत्तक-ग्रहण तथा स्थापन पश्चात् आदि भी शामिल है (संलग्नक - 1)।
- (2) बच्चों और उपस्थित कर्मचारियों का हाजिरी रजिस्टर।
- (3) ब्यौरे के साथ प्रत्याशित दत्तक माता-पिता का रजिस्टर/उसकी प्रति दत्तक-ग्रहण समन्वय एजेंसी तथा राज्य दत्तक-ग्रहण प्रकोष्ठ को प्रत्येक माह भेजी जाएगी।

- (4) बच्चों का रजिस्टर जिसमें उनका आगमन, प्रस्थान, अस्पतालों में भर्ती होना, अपने माता या पिता (माता-पिता) को लौटाया जाना तथा मृत्यु, यदि कोई हो, का ब्यौरा हो ।
- (5) प्रत्येक बच्चे की चिकित्सा स्थिति फाइल और अलग-अलग केस फाइलें । जहां कहीं संभव हो जैविक माता या पिता (माता-पिता) का चिकित्सा रिकार्ड रखा जाएगा ।
- (6) गृह के रख-रखाव से संबंधित रजिस्टर ।
- (7) निर्धारित प्रपत्र में मासिक रिपोर्टें (अनुलग्नक - 2) ।
- (8) दत्तक परिवार के साथ रखे गए बच्चों का कानूनी स्थापन से पहले और कानूनी स्थापन के बाद का अनुवर्ती रजिस्टर ।
- (9) आवश्यक ब्यौरे और आंकड़ों के साथ संगठन की वार्षिक रिपोर्ट ।
- (10) वाउचरों, रोकड़ बही, खाता बही, व्यय विवरण, वार्षिक लेखा, भुगतान रजिस्टर, बैठकों के कार्यवृत्त, अनुदान उपयोग रजिस्टर, परीक्षित लेखा विवरण से संबंधित रजिस्टर ।
- (11) प्रोत्साहन संबंधी कार्यकलापों के दस्तावेज ।
- (12) संगत कानून और लाइसेंसिंग अधिनियम के तहत उल्लिखित अन्य रिकार्ड ।

1.1.14 बच्चों का स्थानांतरण

- (1) एक एजेंसी से दूसरी एजेंसी में बच्चे के स्थानांतरण के लिए, चाहे नगर जिले या अंतर जिले के अंदर ही क्यों न हो, राज्य सरकार के प्राधिकृत अधिकारी जैसे जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट/राज्य सरकार का दत्तक-ग्रहण प्राकोष्ठ की पूर्व अनुमति अपेक्षित है । यह किसी संगठन की शाखाओं से बच्चों के स्थानांतरण के मामले में भी लागू है । जहां कहीं अपेक्षित हो, किशोर न्याय अधिनियम, 2000 में यथा निर्धारित स्थानांतरण की प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा ।

- (2) बच्चे का स्थानांतरण उसके प्रवेश, प्रारंभिक व्यक्तिवृत्त, दस्तावेजी प्रमाण यह सिद्ध करने के लिए कि बच्चा कानूनी रूप से मुक्त है, तथा स्थानांतरण पत्र से संबंधित उपलब्ध दस्तावेजों के साथ होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, बच्चे का फोटोग्राफ, बाल अध्ययन रिपोर्ट, शारीरिक जांच रिपोर्ट तथा अन्य संगत दस्तावेज भेजे जाएं। स्वीकारकर्ता एजेंसी को बच्चे को स्वीकार करने से पूर्व सभी तथ्यों की जांच कर लेनी चाहिए क्योंकि एक बार बच्चे को प्रवेश दे दिया जाता है तो इसके लिए वह कानूनी रूप से उत्तरदायी हो जाएगा।
- (3) बच्चों के अन्तर्राज्यीय स्थानांतरण के मामले में निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जाए:
- (क) किसी अनाथालय/एजेंसी से किसी अन्य राज्य में बच्चों का स्थानांतरण उस राज्य सरकार की अनुमति से किया जा सकता है जिसके क्षेत्राधिकार में बच्चा मूल रूप से निवास कर रहा है।
 - (ख) बच्चे को उसके मूल स्थान में दत्तक ग्रहण के लिए कानूनी रूप से मुक्त बनाया जाए।
 - (ग) निकटतम दत्तक-ग्रहण समन्वय एजेंसी को तथा राज्य दत्तक-ग्रहण प्रकोष्ठ नई एजेंसी में बच्चे को इसके आगमन के 15 दिनों के अंदर पंजीकृत किया जाए।
 - (घ) यदि एजेंसी में बच्चे/बच्ची का उसके प्रवेश के दो वर्षों के भीतर किसी उपयुक्त भारतीय परिवार के साथ दत्तक-ग्रहण में स्थापन न किया जा सके तो उसे निकटतम पंजीकृत भारतीय स्थापन एजेंसी में राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से स्थानांतरित किया जा सकता है। ऐसे अनुरोध को स्वीकार करते समय राज्य सरकार ऐसे पहलुओं को ध्यान में रखे जो केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए जाएं।

1.1.15 अनुवर्तन

जिन बच्चों का दत्तक ग्रहण देश के अंदर किया जाए उनका अनुवर्तन इस प्रकार होगा:

- (1) यदि कोई दत्तक-ग्रहण पूर्व पोषण देखभाल प्रभावित हो तो पोषण देखरेख की नियमित मानीटरिंग होगी और मूल्यांकन किया जाएगा। व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित समाजिक कार्यकर्ता परिवार में नियमित रूप से जाएगा। दत्तक-ग्रहण आदेश को पोषण स्थापन के 6 माह के अंतर्गत प्राप्त किया जाए।
- (2) बच्चों की अनुवर्ती रिपोर्टों की प्रतियां एजेंसी द्वारा संबंधित राज्य सरकार और दत्तक-ग्रहण स्थापन एजेंसी को भेजी जाएंगी।
- (3) एजेंसी देखेगी कि कानूनी दत्तक-ग्रहण शीघ्रातिशीघ्र हो और उसके द्वारा बच्चे के हितों की रक्षा हो।
- (4) कानूनी दत्तक-ग्रहण के बाद एजेंसी परिवार के साथ एक अनुवर्तन कार्य को कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए या न्यायालय द्वारा यथा निर्दिष्ट अवधि के लिए कायम रखेगी।
- (5) एजेंसी द्वारा दत्तकग्राही माता-पिता तथा बच्चे को दत्तक-ग्रहणोत्तर परामर्श दिया जाएगा।

1.1.16 बाल देखभाल गृहों में न्यूनतम मानक

प्रत्येक दत्तक-ग्रहण एजेंसी को अनुलग्नक-4 के अनुसार संस्था में गुणवत्ता वाली बाल देखरेख को बनाए रखना है।

1.1.17 मान्यता प्राप्त भारतीय स्थापन एजेंसियों के मामले में, जब कभी वे देश में दत्तक-ग्रहण से संबंधित मामलों पर कार्रवाई करें, पिछले पैराग्राफों में निर्धारित प्रक्रियाएं तथा देश में दत्तक-ग्रहण से संबंधित अन्य विषय-वस्तु लागू होंगे।

अध्याय - 2

राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों की भूमिका बाल गृहों की सूची**बाल गृहों की सूची**

- 2.1 राज्य सरकारें ('राज्य सरकार' शब्दों में, जहां लागू हो, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन भी शामिल होगा) विभिन्न कानूनों के अंतर्गत पंजीकृत, मान्यता प्राप्त, या लाइसेंस प्राप्त सरकारी/स्वैच्छिक/निजी संगठनों द्वारा निराश्रित, परित्यक्त, अनाथ, अपराधी या उपेक्षित बच्चों के पालन-पोषण के लिए चलाए जा रहे बाल गृहों की एक सूची रखेंगी।

दत्तक-ग्रहण एजेंसियों की सूची

- 2.2 राज्य सरकारें बच्चों के देश में और देश से बाहर दत्तक-ग्रहण को संचालित करने वाली सभी एजेंसियों की सूची भी अलग से रखेगी और उन सभी बच्चों की पहचान करेगी जो कानूनी रूप से मुक्त हैं।
- 2.3 राज्य सरकारें इसमें उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार देश में दत्तक-ग्रहण के लिए भारतीय दत्तक-ग्रहण एजेंसियों को मान्यता देंगी। राज्य सरकारों को लाइसेंस प्राप्त दत्तक-ग्रहण स्थापन एजेंसियों की सूची केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण को वर्ष में एक बार भेजनी चाहिए।
- 2.4 राज्य सरकारों की भूमिका और कार्य

राज्य सरकारें अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत देश में तथा देश से बाहर दत्तक-ग्रहण दोनों को मानीटर करेंगी और देश से बाहर दत्तक-ग्रहण के लिए लाइसेंस प्राप्त स्थापन एजेंसियों, देश में दत्तक-ग्रहण के लिए लाइसेंस प्राप्त दत्तक-ग्रहण एजेंसियों तथा दत्तक-ग्रहण समन्वय एजेंसियों तथा संवीक्षण एजेंसियों के कार्यकलापों का समन्वय करेगी। वे निम्नलिखित कार्य भी करेंगी :

- (1) देश के अंदर परिवारों के साथ दत्तक-ग्रहण या संरक्षकता में पात्र बच्चों के स्थापन को प्रोत्साहित करना और बढ़ावा देना।

- (2) बच्चे को देश से बाहर दत्तक-ग्रहण के लिए स्वतंत्र घोषित करने हेतु दत्तक-ग्रहण समन्वय एजेंसियों के साथ छानबीन करना ।
- (3) अनाथालय और अन्य पूर्त आश्रम (पर्यवेक्षण और नियंत्रण) अधिनियम, 1960 तथा/अथवा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 को लागू करना और/या बाल कल्याण संस्थाओं में बाल देखरेख के लिए कतिपय न्यूनतम मानदंडों को बनाए रखने हेतु उपयुक्त वैकल्पिक नियमों को तैयार करना । जो आश्रम (गृह) राज्य सरकारों द्वारा लाइसेंस/मान्यता प्राप्त नहीं हैं उन्हें दत्तक-ग्रहण कार्य करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए ।
- (4) देश से बाहर दत्तक-ग्रहण हेतु नई मान्यता या मान्यता के नवीकरण के लिए सभी आवेदनों को प्राप्त करें और उचित छान-बीन के बाद या अन्यथा यथा निर्धारित सहायक दस्तावेजों के साथ अपनी स्पष्ट सिफारिश दें ।
- (5) दत्तक-ग्रहण के संबंध में निम्नलिखित सदस्यों की एक सलाहकार समिति का गठन करें

(क)	सचिव, महिला और बाल विकास या दत्तक-ग्रहण कार्यक्रम के लिए प्रशासनिक विभाग	1	अध्यक्ष
(ख)	निदेशक, महिला और बाल विकास या दत्तक-ग्रहण कार्यक्रम के लिए संबंधित निदेशालय	1	सदस्य
(ग)	दत्तक-ग्रहण स्थापन एजेंसियों के दो प्रतिनिधि	2	सदस्य
(घ)	दत्तक-ग्रहण समन्वय एजेंसियों का एक प्रतिनिधि	1	सदस्य
(ङ)	दत्तक-ग्रहण संवीक्षण एजेंसियों का एक प्रतिनिधि	1	सदस्य
(च)	समाज और बाल कल्याण के क्षेत्र में तीन विशेषज्ञ	3	सदस्य

यह समिति बच्चों के क्षेत्र में दत्तक-ग्रहण को बढ़ावा देने के लिए बाल कल्याण के उपायों और अर्थोपायों के बारे में समय-समय पर बैठकें करेगी। इस प्रकार की समिति का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा।

- (6) राज्य सरकार दत्तक-ग्रहण के कार्य के समन्वय, मानीटर और विकसित करने के लिए समाज कल्याण निदेशालय में एक दत्तक-ग्रहण प्रकोष्ठ की भी स्थापना करेगी और दत्तक-ग्रहण संबंधी सलाहकार समिति को लिपिकीय तथा प्रशासनिक सहायता प्रदान करेगी। दत्तक-ग्रहण प्रकोष्ठ में कम से कम एक अधिकारी और एक सहायक तथा राज्य में लाइसेंस प्राप्त और मान्यता प्राप्त एजेंसियों की संख्या के आधार पर एक से अधिक सहायक होने चाहिए।
- (7) देश में दत्तक-ग्रहण के लिए समाज/बाल कल्याण एजेंसियों को लाइसेंस देने/लाइसेंस निलम्बित/समाप्त करने के लिए उपयुक्त मानदंड तैयार करें।
- (8) सुनिश्चित करें कि 1984 के एल.के. पाण्डेय बनाम भारत संघ मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के प्रावधान तथा भारत सरकार द्वारा दत्तक-ग्रहण के लिए समय-समय पर जारी किए गए दिशा-निर्देशों का पालन किया जाए।
- (9) राज्य सरकार सभी दत्तक-ग्रहण एजेंसियों और बाल गृहों से बच्चों के नए आगमन तथा मृत्यु संबंधी आंकड़े प्राप्त करेगी।
- (10) राज्य सरकार प्रत्याशित दत्तक माता-पिता की सूची और रजिस्टर बनाए रखेगी।
- (11) नर्सिंग होम/अस्पतालों से बच्चों का स्थापन करना गैर-कानूनी और वर्जित है। इस संबंध में उच्चतम न्यायालय के निर्देश को सख्ती से लागू किया जाए और संबंधित राज्य सरकार द्वारा उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए जो इन दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हैं।

- (12) जहां कहीं आवश्यक हो, राज्य सरकार प्रत्याशित दत्तक माता-पिता गृह अध्ययन रिपोर्टें संलग्न-6 में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार अपने पदनामित अधिकारियों द्वारा तैयार करवाएंगी जो सभी दत्तक-ग्रहण एजेंसियों को स्वीकार्य होंगी।
- (13) देश के अंदर विशेष जरूरतमंद बच्चों को गोद लेने के इच्छुक माता-पिता के लिए आयु-मानदंडों में छूट देने के लिए स्वीकृति हेतु विचार करें।

2.5 दत्तक-ग्रहण एजेंसियों का निरीक्षण

राज्य सरकार समय-समय पर और वर्ष में कम से कम एक बार देश से बाहर दत्तक-ग्रहण के लिए लाइसेंस प्राप्त सभी स्थापन एजेंसियों तथा देश में दत्तक-ग्रहण के लिए लाइसेंस प्राप्त दत्तक-ग्रहण एजेंसियों और साथ ही उनके कागज-पत्रों, दस्तावेजों तथा बच्चों से संबंधित सेवा से जुड़े कार्यकलापों का सामान्यतः निम्नलिखित की जांच करने के लिए निरीक्षण करेगी या निरीक्षण करवाएगी:

- (1) दत्तक-ग्रहण, संगठन द्वारा बच्चों के हित में एक कल्याणकारी उपाय के रूप में किया जा रहा कार्यकलाप है न कि एक वाणिज्यिक कार्यकलाप है।
- (2) गृहों में प्रवेश दिए गए बच्चों के लिए उचित रिकार्ड रखे जा रहे हैं।
- (3) प्रवेश दिए गए बच्चों को संस्था में उनकी देखभाल, शिक्षा और विकास के लिए गुणवत्ता वाली देखभाल तथा आधारभूत सुविधाएं दी जाएं।
- (4) बच्चे को गोद लेने या बच्चे को संरक्षण में लेने के इच्छुक व्यक्तियों की सूची संगठन द्वारा नियमित रूप से रखी जाएगी।
- (5) संगठन के लेखे विलम्ब किए बिना रखे जाएं और वार्षिक आधार पर संपरिक्षित किए जाएं, और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट इसकी पुष्टि करे कि लेखे उचित और सही हैं; वह संगठन जिसे विदेशी वित्त-पोषण मिलता हो गृह मंत्रालय द्वारा विधिवत पंजीकृत हो और अन्यथा जिसने विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 1976 के उपबंधों का पालन किया हो।

- (6) संगठन दत्तक-ग्रहण में दिए गए बच्चों के कल्याण के बारे में नियमित प्रगति रिपोर्टें प्राप्त कर रहा हो ।
- (7) एजेंसी द्वारा बालकों की देखरेख का पर्यवेक्षण करने के लिए अर्हता प्राप्त कर्मचारी काम पर लगाए गए हों ।
- (8) प्रत्याशित दत्तक माता या पिता (माता-पिता) के साथ दत्तक-ग्रहण पूर्व पोषण देखभाल में रखे गए बच्चों के मामले में, इस प्रकार के स्थापन के 6 माह के अंदर मामले को कानूनी रूप दे दिया गया हो ।
- (9) प्रत्याशित दत्तक-ग्रहण माता या पिता (माता-पिता) का एक केन्द्रीय रजिस्टर रखा जाता हो ।
- (10) सभी मामलों में दत्तक-ग्रहण पूर्व पोषण देखभाल में दिए गए बच्चों के लिए एक अलग रजिस्टर रखा जाता हो ।

2.6 कार्य-निष्पादन की मानीटरी

राज्य सरकार दत्तक-ग्रहण कार्य में लगी सभी देश के बाहर दत्तक-ग्रहण के लिए लाइसेंस प्राप्त स्थापन एजेंसियों/देश में दत्तक-ग्रहण के लिए लाइसेंस प्राप्त दत्तक-ग्रहण एजेंसियों से इन एजेंसियों की कार्य-प्रणाली को मानीटर करने के लिए प्रत्येक तिमाही की सूचना और आंकड़े मंगाएगी । केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किए जाने वाले प्रपत्र में आंकड़े मंगाए जाएंगे । सभी लाइसेंस प्राप्त दत्तक-ग्रहण स्थापन एजेंसियों से वार्षिक रिपोर्ट और लेखों का संपरिक्षित विवरण प्राप्त किया जाएगा ।

2.7 देश से बाहर दत्तक-ग्रहण के लिए लाइसेंस प्राप्त स्थापन एजेंसी/देश में दत्तक-ग्रहण के लिए लाइसेंस प्राप्त दत्तक-ग्रहण एजेंसी की मान्यता/लाइसेंस का निलंबन/समापन

देश से बाहर दत्तक-ग्रहण के लिए लाइसेंस प्राप्त स्थापन एजेंसी/देश में दत्तक-ग्रहण के लिए लाइसेंस प्राप्त दत्तक-ग्रहण एजेंसी द्वारा कदाचार की रिपोर्ट के मामले में राज्य सरकारें केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण को सूचित

करेगी और उचित कार्रवाई करेगी। वह चूककर्ता एजेंसियों के विरुद्ध की गई किसी कार्रवाई के द्वारा प्रभावित हुए बच्चों के लिए उपयुक्त पुनर्वास योजना तैयार करेगी। सामान्यतः ऐसे बच्चों को अन्य एजेंसियों को स्थानांतरित किया जाना चाहिए। राज्य सरकारें सुनिश्चित करेंगी कि कोई संगठन या तो देश से बाहर दत्तक-ग्रहण के लिए लाइसेंस प्राप्त स्थापन एजेंसी या देश में दत्तक-ग्रहण के लिए लाइसेंस प्राप्त दत्तक-ग्रहण एजेंसी किसी ऐसी गैर-कानूनी गतिविधि या प्रथा में लिप्त न हो जो कानून के विरुद्ध हो और बच्चे के हित में न हो। अतः यह आवश्यक है कि राज्य सरकारें अपने-अपने राज्यों में दत्तक-ग्रहण एजेंसियों के कार्यकलापों की मानीटरी में पूरी सावधानी और सतर्कता बरतें।

शब्दावली

दत्तक-ग्रहण: दत्तक-ग्रहण परिवार बनाने की एक विधि है, जिसमें दत्तक-ग्रहण माता-पिता के साथ बच्चे का स्थापन शामिल है। इसके लिए एक कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा जिससे यह स्थापित हो कि वह उन दत्तक माता-पिता से पैदा हुआ/हुई है।

देश में दत्तक-ग्रहण: भारत में रह रहे भारतीय माता या पिता (माता-पिता) द्वारा भारतीय बच्चे का दत्तक-ग्रहण।

देश से बाहर दत्तक-ग्रहण: दत्तक माता या पिता (माता-पिता) भारतीय मूल के व्यक्तियों और अनिवासी भारतीयों द्वारा किसी भारतीय बच्चे का कानूनी स्थापन।

एच.ए.एम.ए.	-	हिन्दू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम, 1956
जी.ए.डब्ल्यू.ए.	-	संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890
जे.जे.एक्ट-2000	-	किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000

केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (सी ए आर ए): दत्तक ग्रहणों के मामले में केन्द्रीय प्राधिकरण के रूप में कार्य करने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत स्वायत्त निकाय।

देश से बाहर दत्तक-ग्रहण के लिए मान्यता प्राप्त भारतीय स्थापन एजेंसी (आर आई पी ए): देश से बाहर दत्तक ग्रहण में भारतीय बच्चों के स्थापन के लिए केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त भारतीय समाज/बाल कल्याण एजेंसी।

देश में दत्तक-ग्रहण के लिए लाइसेंस प्राप्त दत्तक-ग्रहण स्थापन एजेंसी (एल ए पी ए): देश में दत्तक-ग्रहण के लिए राज्य सरकार द्वारा लाइसेंस/मान्यता प्राप्त भारतीय समाज/बाल कल्याण एजेंसी ।

दत्तक-ग्रहण समन्वय एजेंसी (ए सी ए): दत्तक-ग्रहण समन्वय एजेंसी, केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त संगठन होगी । यह सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होगी और इसके क्षेत्राधिकार में कार्यरत विभिन्न दत्तक-ग्रहण एजेंसियां इसके सदस्य होंगी । इसका मुख्य उद्देश्य देश के अंदर दत्तक-ग्रहण को बढ़ावा देना है ।

दत्तक-ग्रहण संवीक्षण एजेंसी (ए एस ए): देश के अंदर और देश से बाहर दत्तक-ग्रहण के लिए दत्तक-ग्रहण संबंधी आवेदनों की जांच करने हेतु न्यायालय द्वारा नियुक्त स्वतंत्र समाज/बाल कल्याण एजेंसी ।

बाल कल्याण समिति (सी डब्ल्यू सी): देखभाल और संरक्षण के जरूरतमंद बालकों के संबंध में किशोर न्याय अधिनियम, 2000 में यथा-परिभाषित समिति ।

किशोर न्याय बोर्ड (जेजे बी): किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 के अंतर्गत यथा-गठित किशोर न्याय बोर्ड ।

बाल अध्ययन रिपोर्ट (सी एस आर): इसमें बालक, इसकी जन्म-तिथि, सामाजिक पृष्ठभूमि आदि का ब्यौरा होगा ।

गृह अध्ययन रिपोर्ट (एच एस आर): इसमें दत्तक युगलों की सामाजिक स्थिति एवं पारिवारिक पृष्ठभूमि; गृह का वर्णन, जीवन-स्तर; जीवन साथी एवं परिवार के सदस्यों के साथ संबंध, स्वास्थ्य संबंधी विवरण, आर्थिक स्थिति आदि का ब्यौरा होता है ।

शारीरिक जांच रिपोर्ट (पी ई आर): इसमें बच्चे की चिकित्सा रिपोर्ट, उपचार संबंधी रिपोर्ट, यदि कोई हो आदि शामिल होगी ।

पी ए पी: प्रत्याशित दत्तक माता-पिता ।

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT**NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st June, 2004

S.O. 711(E).— In-country adoption Guidelines were earlier circulated for the first time to all State Governments vide letter No. 1-4/98-CARA dated 14.9.1998. Subsequently, circulars have been issued to State Governments from time to time on matters relating to licensing of residential homes, setting up of State Adoption Units, State Advisory Boards and monitoring of activities of adoption agencies etc. Instructions have also been issued to adoption agencies, so that common adoption practices are followed throughout the country.

It has been felt that there is a need for a revised set of guidelines to regulate in-country adoptions so that common practices and norms can be ensured for adoption all over the country. The new set of guidelines cover issues relating to adoption fees, age criteria for adoptive parents, home study etc. It is hoped that these guidelines will facilitate in-country adoption of children who are abandoned, destitute or orphaned so that they get the opportunity to develop in a loving and caring home environment that is the right of every child.

[No. 18-8/2003-CW]

MRS. RAJWANT SANDHU, Jt. Secy.

GUIDELINES FOR IN-COUNTRY ADOPTION – 2004**CONTENTS****Chapter I**

Introduction & Procedures

Chapter II

Role of State Government/UT Administration

CHAPTER-I

INTRODUCTION & PROCEDURES

In pursuance of its constitutional mandate, the Government of India has evolved a National Policy for the Welfare of Children. The thrust of this policy is summed up in the following words:

"The Nation's children are a supremely important asset. Their nurture and solicitude are our responsibility. Children's programme shall find a prominent part in our national plans for the development of human resources, so that our children grow up to become robust citizens, physically fit, mentally alert and morally healthy, endowed with the skills and motivations needed by society. Equal opportunities for development to all children during the period of growth should be our aim, for this would serve our larger purpose of reducing inequality and ensuring social justice."

Following upon the above mandate, the Govt. of India has evolved several programmes to ensure the betterment of children and their development in a wholesome manner. The Ministry of Social Justice & Empowerment, Govt. of India has been mandated, amongst others, with the welfare of children in difficult circumstances. The rehabilitation of such children through adoption is one of the major planks of the Ministry's policies for children. This policy keeps in mind the fact that the full and wholesome growth of a child is possible only in an atmosphere of parental love and guidance. It recognizes the family as the Central fulcrum around which both mental and physical development of a child is given full opportunity to blossom.

In pursuance of land-mark judgement of the Supreme Court of India in the Laxmi Kant Pandey Vs. Union of India case of 1984, the Central Adoption Resource Agency (CARA) was established by the Ministry and subsequently the Revised Guidelines for the Adoption of Indian children were issued in 1995 to provide a frame work of Rules for regulating and monitoring inter-country adoptions. These Guidelines are now applicable all over the country and they provide a uniform mechanism for processing cases of Inter-country adoptions. Of late the Ministry has been contemplating the need to provide a similar framework of Guidelines for monitoring and processing of in-country adoptions. Both the Supreme Court in its above judgement and the United Nations Declaration of the Rights of the Child adopted by the General Assembly of the United Nations in 1989 as well as the Hague Convention on Inter-country adoption of 1993 clearly lays down that the best interest of the child without a family is served by providing it an opportunity to be placed with a family within its own socio cultural milieu. Thus every child has a right to be considered for placement with a family belonging to its own national and cultural background within the country. Inter-country adoption is therefore, to be seen as an option, which is to be considered only when the above is not possible. This is also prescribed in the Guidelines governing inter-country adoptions.

The importance of In-country adoption is, self-evident. There is need to ensure that not only In-country adoption is actively encouraged and propagated throughout

the country, but also a well formulated procedure is formulated and followed for the purpose. The Ministry of Social Justice and Empowerment, Govt. of India has now decided to issue common Guidelines for the procedure that needs to be undertaken by adoption Homes/Institutions before filing adoption petitions under Hindu Adoption and Maintenance Act, 1956 (HAMA), Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act, 2000 (JJ Act) and also Guardianship Petitions under Guardians & Wards Act, 1890 (GAWA). These Guidelines do not affect the provisions in the existing Acts and laws but serve to provide a procedure for processing adoption cases before they are actually brought before the competent authorities/courts under the afore-mentioned Acts for orders. The Guidelines will also ensure that the best interests of the child are protected and all adoptions are legally processed through licensed Homes/Institutions only.

The Central Adoption Resource Authority is the nodal body of the Ministry of Social Justice & Empowerment to deal with all adoption matters. After due consideration of all aspects and consultations with experts in this field, the Government of India, hereby issues the Guidelines for In-country Adoption that shall come into effect immediately and will supercede this Ministry's earlier Circular No.1-4/98 (CARA) Dt.14.09.1998. The Ministry of Social Justice & Empowerment, Government of India, reserves to itself the power, at its discretion to make such amendments, additions, deletions or alternations in these Guidelines as are deemed necessary from time to time.

AIMS & OBJECTS :

The Guidelines for In-country adoption aim:

- to regulate and facilitate a common procedure for In-country adoptions throughout the country;
- to encourage adoption of destitute & orphan children within the country.

1.1 ADOPTION HOMES

1.1.1 Role & Functions of LAPAs

- (i) All such Licensed Adoption Placement Agencies for In-country adoptions will be registered under the Societies Registration Act, 1860. They will adhere to any guideline or rule laid down by the State Government/Central Government governing in-country adoption from time to time. As such they will obtain license from the State Government to run child care homes and recognition/permission to place children in adoption within the country and will be known as Licensed Adoption Placement Agencies (LAPAs). Adoption Homes which have been recognised to also undertake inter-country adoption by the Govt. of India will be called Recognised Indian Placement Agencies (RIPAs)
- (ii) Details of all Children admitted by LAPAs will be entered in the admission register in the format prescribed.

- (iii) All LAPAs will be members of the nearest Adoption Coordinating Agency.
- (iv) They will maintain a separate list of Indian couples/individuals registered with them as prospective adoptive parent(s).
- (v) All the LAPAs must have a high standard of child care facilities and observe prescribed & adequate standards in child care as per the broad criteria. For children, between 3 and 6 years proper recreational and pre-school educational facilities must be provided.
- (vi) It will be mandatory for all the LAPAs to have qualified staff. The following staff should be available in a home for 10 children:

1. Superintendent	-	1
2. Nurse-cum-supervisor	-	1
3. Full time or part time Doctor preferably Pediatrician		- 1
4. Social Worker	-	1
5. Ayas	-	4 for 10 children
6. Accounts and Administrative staff		- 1
7. Chowkidar	-	1

The above is the recommended staff structure and it may vary in proportion to the number of children and size of the Home. The professional staff such as Nurses and Social Workers should have the relevant qualifications such as Degree/Diploma in Nursing and MSW/BSW respectively.

- (vii) Every LAPA has a moral and legal responsibility to function within the ambit of the law and in the best interest of the child. While admitting an orphan or destitute child, the Home will give a name to the child, record briefly the social background of the child, record identification marks of the child, record height and weight of the child, conduct medical examination of the child and get the child photographed. In case of all new arrivals, the local authority should be informed within 24 hours and in case of admission of any abandoned child, the Home will file FIR with the nearest Police Station and inform the local authority and the CWC within 24 hours.
- (viii) A monthly report on the number of children available will be submitted to the State Adoption Cell of the State Govt. The death of any child will also be reported to the local authority, ACA & State Adoption Cell immediately, giving details, within 48 hours. The Death Certificate alongwith the photograph, shall be kept in the personal record file counter signed by the Office bearer of the LAPA. Every LAPA shall maintain a separate file for each child with the child's complete case history. Every child should have a Child Study Report which shall be shown to the prospective adoptive parents. Format of such a report is placed.

- (ix) All registered prospective adoptive parent(s) may avail counseling facilities which is to be given free by the LAPA. They should be counselled in detail and made aware of the legal obligation to be placed upon them once a child has been adopted, the rights of the child itself, the various Acts under which a child can be placed with the family, procedures for obtaining birth certificate etc.
- (x) The LAPAs will submit a list of children available with them with relevant information every month to the ACA and State Adoption Cell to facilitate search for suitable adoptive parent(s) who may be registered with them.
- (xi) While filing an application for adoption or placement of a child in the appropriate Court, the LAPA will also be a co-respondent. The child will be in the custody of the LAPA until the final placement takes place through the Court order. Therefore, parent(s) cannot directly file a petition and the details of the biological unwed mother cannot be disclosed to the parent(s) as a part of the petition. If violation of these provisions come to notice, action will be taken against the LAPA by the State Government. The surrender document should be treated as confidential and submitted only to the court. The LAPA must ensure that adoption petitions are filed in the court expeditiously and render all cooperation to the court for obtaining early orders.
- (xii) The LAPA will send a monthly report to the ACA and the State Adoption Cell.

1.1.2 Mode of Admission of children to LAPA

A child can be admitted to the LAPA by two modes:

- (i) Direct surrender by biological parent(s)/unwed mother.
- (ii) Child abandoned in the LAPA or abandoned elsewhere & brought by a third party or police or referred by the Child Welfare Committee.

1.1.3 Surrender of a Child by biological parent (s)

- (i) In the case of surrender of a child, the biological parent(s) should be counselled and duly informed by the LAPA concerned of the effect of their decision and the alternatives available for the care and maintenance of the child. No LAPA will directly or through agents, attempt to persuade the biological parent(s) to surrender their children with monetary or other incentives.
- (ii) The surrender document should be executed truly by the biological parent(s) with no compulsion, payment or compensation of any kind by anyone.
- (iii) The parent(s) should be informed by the LAPA of their right to reclaim the child within 60 days from the date of the surrender. They should be made aware that after the period of 60 days the surrender documents will become irrevocable and

the child will be considered free for adoption and the LAPA will be free to place the child in adoption or guardianship.

- (iv) The surrender document should be executed on stamp paper in the presence of two responsible witnesses of whom one should be responsible person who is not an employee of the organization. The documents will also be signed by a Notary/Oath Commissioner. The LAPA should be able to produce these witnesses if the necessity arises. The responsibility for the authenticity of the surrender document would be on the LAPA. In case of a minor surrendering a child, at least one signature(s) of parent(s)/relative(s) of the minor should be obtained in the presence of the minor. The State Govt. will have the right to cross check all surrender documents and copies of these are to be sent to the Adoption Cell/Department. During the surrender process, the LAPA should ensure that:
 - (a) If a child born in wedlock is surrendered, both parents sign the surrender document and in case a parent(s) is dead, proof of death is furnished. Where the death certificate is not available, a certificate from local Sarpanch/Panchayat/Govt. Authority should suffice.
 - (b) In case of a child born out of wedlock, the mother herself and none else can surrender the child. If she is a minor, the signature of an accompanying relative will be obtained on the surrender document.
 - (c) If the surrender is effected by any person other than the biological parent(s), the same procedure is followed as that for an abandoned child under the JJ Act 2000, since the child will be treated as abandoned.
 - (d) When a child is born to a married couple but is surrendered by one biological parent and the whereabouts of the other are not known the same procedure is followed as that for an abandoned child.
 - (e) If the document of surrender is considered invalid/incomplete by the State Govt. it may direct the concerned Agency to follow the same procedure as under the JJ Act-2000. Any such direction should however be communicated to the Agency within 15 days of receiving the copy of the surrender documents.

1.1.4 Abandoned Child

(i) The procedure regarding abandoned children is prescribed by the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act-2000. While the CWC (Child Welfare Committee) is the final authority to dispose of cases for the care, protection, treatment, development and rehabilitation of the children (Section 31.1 of the said Act), a child can be produced before the Committee by the following persons (Section 32.1 of the said Act):

- a) any police officer or special juvenile police unit or a designated police officer;

- b) any public servant;
- c) Childline, a registered voluntary organisation or by such other voluntary organisation or an agency as may be recognised by the State Government;
- d) any social worker or a public spirited citizen authorised by the State Government; or
- e) by the child itself.

(ii) Wherever a LAPA receives an abandoned child under its care it will immediately file a First Information Report in the concerned Police Station and make an application to CWC within 24 hours seeking permission to keep custody of the child.

(iii) The LAPA may initiate the process of clearance from CWC (Child Welfare Committee) at the earliest, in the case of abandoned children and the Child Welfare Committee will make all possible efforts within a period of two months to declare the child legally free for adoption.

(iv) In the case of abandoned children the procedure for declaring such children as legally free for adoption as laid down under the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000 shall apply. An abandoned child can be given in adoption only when the Child Welfare Committee under the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000, declares such a child to be legally free for adoption. An abandoned child will be legally free for adoption when such an order is signed by at least two members of the Child Welfare Committee as per Sec. 41(5)(a) of the JJ Act. 2000. On receipt of a report under section 32, the Committee or any police officer or special juvenile police unit or the designated police officer shall hold an inquiry in the prescribed manner and the Committee, on its own or on the report from any person or agency as mentioned in sub-section (1) of section 32 of JJ Act-2000, may pass an order to send the child to the children's home for speedy inquiry by a social worker or child welfare officer. The inquiry under this section will be completed within such shorter period as may be fixed by the Committee.

(v) Where there is no CWC functioning, the District Collector or any other authority empowered by the State Government for the purpose may issue the Certificate of Abandonment.

1.1.5 Procedure For Incountry Adoption:

Stage I

- Prospective adoptive parent(s) should register themselves with the local RIPA/LAPA or Adoption Coordinating Agency or with the State Adoption Cell.

Stage II

- A home study report of the prospective adoptive parents will be prepared by the social worker of the Agency. To allay the fears and apprehensions of the prospective adoptive parent(s), pre-adoptive counselling sessions will be undertaken by the social worker during the preparation of the home study report. Assessing the ability of a couple to parent a child not born to them is of crucial importance in a successful adoption. Therefore, their suitability to care for an unrelated child is assessed through this home study and counselling. Documents relating to the financial and health status of the prospective parent(s) will be part of the Home Study Report.
- In case of Inter-State adoption applications by parent(s), they will be accompanied by Home Study prepared by a qualified social worker working in a RIPA/LAPA. Where State Govt.'s have officially delegated such work for its officials, the Home Study Report could be prepared by the concerned official.
- Criteria for eligibility of parent(s) will be adhered to, as stated in Para 1.1.7.
- The Agency will make a suitable reference from amongst the admitted children legally free for adoption. If no suitable child is available, the family will be referred to the ACA.

Stage III

- After a Home Study has been accepted and approved, a child will be shown to the parent(s). The agency will take care to match a child meeting the description, if any, desired by the parent(s).
- In case of placement of older children (above the age of 6), both written and verbal consent of the child will be obtained.

Stage IV

- Once a successful matching has been done, the agency will file a petition in the Court/JJB for obtaining the necessary orders under the relevant Act. The above process will normally be completed in 6-8 weeks.

Adoption under which Act

The child can be legally placed with the parent(s) under HAMA/GAWA/JJ-Act 2000. The prospective parents should be informed about the different Acts available and the ramifications of each one. It would be left to them to decide as to which Act they would like to file their petition under, provided that they are eligible to do so under the chosen Act. As stated above, the prospective parents must be made to fully understand the status of their adoption under each Act.

Follow up visits

Once an order has been issued, it should be followed by regular follow-up visits and post adoption counseling by the social worker till the child is adjusted in the new environment. The follow up should preferably be for a period of one year at least or as directed by the Court/JJB. Copies of the follow-up reports will be sent

to the District Social Welfare officer/concerned State Government Department, concerned Scrutiny Agency and the Court/JJB from where the order was obtained.

1.1.6 Adoption Costs

Maintenance charges shall not exceed Rs.15,000/- at the rate of Rs.50/- per day from the date of admission to till the child is placed in pre-placement foster care. In case of special medical care, hospitalization charges subject to a maximum of Rs.9000/- may be claimed on production of actual bills. Legal fees and scrutiny fees will be charged on actuals. **NGOs and Government Homes getting Grant-in-aid from the Central Government under Sishu Greh Scheme can claim maintenance and legal fee from the adoptive parents only as per the provisions laid down in Para 5.4 of the Scheme.** The Fee structure for in-country adoptions has also been drawn up to establish a uniform base for the whole country (The prescribed fees will however be subject to any direction given in this regard by the court issuing the Adoption Order). In addition to the above charges the agency can claim Rs.200/- as registration charges in each case from adoptive parents and Rs.1000/- for preparing Home Study Reports.

1.1.7 Criteria for Prospective Adoptive Parents:

- a) Marital Status, Age and Financial Status with reasonable income to support the child and clear police record should be evident in the Home Study Report.
- b) Prospective adoptive parents having composite age of 90 years and less and where neither parent has crossed 45 years can be considered for adoption of Indian children. These provisions may be suitably relaxed in exceptional cases for reasons clearly stated in the Home Study Report. However, in no case should the age of the prospective adoptive parent(s) exceed 55 years.
- c) In case of Special Needs children with medical problems, the age limit of adoptive parent(s) may be relaxed by concerned State Government.
- d) Single persons who have not crossed the age of 45 years and who fulfill the other criteria can also adopt.
- e) The prospective parent(s) should have a regular source of income with a minimum average monthly income of at least Rs.3000/- per month. However, lower income will be considered taking into account other assets and support system i.e. own house etc.
- f) All the criteria mentioned above for adoptive parents will also apply to **single parents** with the additional requirements given below:-

1. Age: Age of the adoptive single parent should be above 30 years and below 45 years.
2. Age Difference: The age difference between the adoptive single parent and adoptive child should be 21 years.
3. Family: The single parent should have additional family support system.

1.1.8 Criteria for eligible children:

- The child should be legally free for adoption.
- Siblings/twins/ triplets etc. should not be separated.

- The consent of children above 6 years should be taken for the adoption.

1.1.9 Procedure for Home Study Reports (HSR)

The LAPA & ACAs may follow the following procedure for preparing the Home Study Reports:

1. It should be prepared only after Registration of the parent(s).
2. It should be prepared by a qualified Social Worker or designated officer of the State Govt. after interviewing both parents individually and together.
3. Other members of the family, if they live in a joint family should also be interviewed.
4. Parent(s) should be counselled on adoption issues including open adoption.
5. All necessary documents, marriage certificate, proof of income etc. should be checked and annexed to the Report.

1.1.10 Safeguards

The following safeguards should be ensured while placing the child in In-country Adoption:

- a) The child should be legally free for adoption.
- b) The two months reconsideration period should be observed for a relinquished child.
- c) All efforts to trace the biological parent(s) should be made as per the prescribed framework for abandoned children
- d) Priority should be given to applicants already registered with the Agency and they should be regularly informed of the status of their applications.
- e) The Child Study Report along with PER should be signed by both adoptive parents.
- f) The parent(s) should be advised to have the child assessed by their own doctor in case of doubts.
- g) A receipt should be issued for the adoption fee.
- h) Older children above 6 years – special clearance from State Government should be obtained.
- i) In case of prospective adoptive parent(s) willing to adopt a child with disability/health problem, a document stating the same shall be obtained.
- j) Placement of girls with a single male is not allowed as also placement of children with same sex couples.
- k) Siblings and twins etc. should not be separated. Prospective Adoptive Parent(s) should be made aware of this.
- l) The prospective adoptive parent(s) may take the child on pre-adoption foster care signing a Foster Care Affidavit only when the case is filed in the Court.
- m) The prospective adoptive parent(s) should fulfill the laid down criteria of age, income etc.
- n) Above all, the Agency must satisfy itself that the proposed adoption is in the best interest of the child.

1.1.11 Court Procedure:

- (i) The adoption petition along with the relevant documents should be filed before the concerned Family Court/District Court/JJB as the case may be by the Adoption Agency.
- (ii) The Court/JJB at its discretion may refer the petition to Scrutiny Agencies in their respective jurisdiction.

1.1.12 Birth Certificate:

The date of birth of the abandoned child being given in adoption will be recorded in the order of the Juvenile Justice Board. In all other cases where the child has not been adopted or its adoption has not been carried out under the JJ Act and its date of birth has not been recorded officially anywhere, the Adoption Agency concerned must make an application to the local Magistrate along with any other material which the Adoption Agency considers relevant in the form of an affidavit made by a responsible person belonging to the Adoption Agency. The local magistrate will then pass an order approving the particulars to be entered in the birth certificate and on the basis of the magisterial order, the requisite certificate will be issued by the local birth certificate issuing authority of the city/town/area where the child has been found. This process shall be initiated only after the adoption is finalized, so that the particulars of the adoptive parents are available for inclusion in the certificate. In case the child has attained the age of three, and the adoption has still not been finalized, the Agency may obtain a birth certificate, if it is found necessary, after informing the court in the form of an affidavit:

- (a) That to the best of its knowledge the child has attained the age of three years;
- (b) That his/her adoption has not been finalized and is likely to take some time or may never be finalized in all probability;
- (c) That a certificate is required for educational/medical/legal purposes or any other reasonable purpose which may be specified; and
- (d) That person(s) will stand in as local parents to the child (this person/these persons shall be a responsible person/responsible persons belonging to the agency) till such time he/she attains majority, or is adopted, whichever is earlier. In such cases a second birth certificate may be issued after adoption to provide for a change in the name/names of the child and the adoptive parent(s) after obtaining an order to that effect from the court, which had passed order for issuing the original birth certificate.

1.1.13 Records and Documents to be maintained by the LAPA

Every registered LAPA will maintain the following records and registers:

- (i) Admission register – All details pertaining to the child including its arrival date of birth, procedure for making the child legally adoptable, pre adoption foster care, adoption and post placements etc.

- (ii) Attendance register of the children and staff present.
- (iii) Register of prospective adoptive parents with details. The copy of the same will be submitted to ACA and State Adoption Cell every month.
- (iv) Register of children showing their arrival, departure, admission into hospitals, restoration to their parent(s) and death, if any.
- (v) Medical case file of each child and individual case files. Wherever possible medical records of the biological parent(s) will be maintained.
- (vi) Registers pertaining to maintenance of the Home.
- (vii) Monthly reports in the prescribed format.
- (viii) Follow-up register of children placed with the adoptive family prior to legal placement and after legal placement.
- (ix) The annual report of the organization together with the necessary details and statistics.
- (x) Registers pertaining to vouchers, cashbook, ledger – expenditure statement, Annual Accounts, payment registers, records of Minutes of Meetings, Grants Utilization Register and Audited Statement of Accounts.
- (xi) Documents of promotional activities.
- (xii) Other records stipulated under the relevant Law and Licensing Act.

1.1.14 Transfer of Children:

- (i) For transfers of children from one agency to another whether within the city, district or inter-district, the prior permission of the authorized official of the State Government such as District Social Welfare Officer/District Magistrate/Adoption Cell of the State Government is required. This is applicable in case of transfer of children from branches of the same organisation also. Wherever applicable, the procedure of transfer will be followed as laid down in JJ Act. 2000.
- (ii) The transfer of the child should be accompanied by available documents pertaining to its admission, preliminary case history, documentary evidence to prove that the child is legally free for adoption, and a letter of transfer. In addition, the photograph of the child, CSR, PER and other relevant documents should be sent. The accepting Agency should verify all the facts before accepting the child, as it will be legally responsible for it, once the child is admitted.

- (iii) In the case of inter-state transfer of children, the following procedures should be followed:
- a) Children from any orphanage/agency may be transferred to another State with the permission of the State Government in whose jurisdiction the child is originally residing.
 - b) A child should be legally made free for adoption in the place of origin.
 - c) The child should be registered with the nearest ACA and State Adoption Cell within 15 days of its arrival in the new Agency.
 - d) If a child cannot be placed in adoption with a suitable Indian family within 2 years of his or her admission into the Agency, he or she may be transferred to the nearest Recognised Indian Placement Agency(RIPA) with the prior permission of the competent authority of the State Government. The State Government, while examining such requests may take into consideration such aspects that may be prescribed by CARA from time to time.

1.1.15 Follow-up

The follow-up of children placed within the country will be as follows:

- (i) If any pre-adoption foster care is effected, there will be regular monitoring and evaluation of the foster care. A professionally trained social worker shall visit the family regularly. The Adoption Order should be obtained within 6 months of the foster placement.
- (ii) The copies of the follow-up reports of the children shall be submitted by the Agency to concerned State Government and ACA.
- (iii) The Agency shall see that legal adoption is effected at the earliest, thereby safeguarding the interest of the child.
- (iv) After legal adoption, the Agency shall maintain a follow-up with the family for a period of at least one year or as stipulated by the Court.
- (v) Post-adoptive counseling shall be provided by the agency to the adoptive parent(s) and the adoptee.

1.1.16 Minimum standards in Child Care Homes:

Each adoption agency has to maintain Quality Child Care in the institution.

- 1.1.17. In the case of RIPAs, the procedures and other matters relating to In-country adoptions laid down in the preceding Paras will apply to them whenever they process cases for in-country adoptions.

CHAPTER II

ROLE OF STATE GOVERNMENT/UNION TERRITORIES

List of Children's Home

- 2.1 The State Governments (the term "State Government" will also include Union Territory Administration wherever applicable) will maintain a list of all children's homes being run for the maintenance of destitute, abandoned, orphaned, delinquent or neglected children by Govt./voluntary/private organisations which are registered, recognised or licensed under various Laws.

List of Adoption Agencies

- 2.2 The State Government shall also separately maintain a list of all Agencies handling in-country and inter-country adoption of children and will identify all children who are legally free for adoption in these institutions.
- 2.3 The State Governments shall recognise Indian adoption agencies for in-country adoption as per the procedure laid down herein. State Governments should send a list of the Licensed Adoption Placement Agencies (LAPA) to CARA once a year.

2.4 Role and Functions of State Governments

The State Govts. will monitor both the in-country and inter-country adoption programme within their jurisdiction and coordinate the activities of RIPAs, LAPAs, ACAs and Scrutinizing Agencies. They will also undertake to:

- (i) Encourage and promote placement of eligible children in adoption or guardianship with families within the country.
- (ii) Scrutinise with ACA applications for declaring a child free for inter-country adoption.
- (iii) Enforce the Orphanages and Other Charitable Homes (Supervision and Control) Act, 1960 and/or Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act, 2000 and/or formulate suitable alternate rules in order to maintain certain minimum standards for child care in child welfare institutions. Homes not licensed/recognised by the State Governments should not be allowed to carry out adoption work.
- (iv) Receive all applications for fresh recognition and renewal of recognition for inter-country adoption and after due verification give its clear recommendation or otherwise with supporting documents as prescribed.
- (v) Form an Advisory Committee on adoption with the following members:

(a)	Secretary, Women & Child Development or the Administrative Department for Adoption Programme	1	Chairman
(b)	Director, Women & Child Development or the concerned Directorate for Adoption Programme.	1	Member
(c)	Two representatives of Adoption Placement Agencies.	2	Member
(d)	One representative of ACAs	1	Member
(e)	One representative of Adoption Scrutinising Agencies.	1	Member
(f)	Three experts in the field of Social and Child Welfare.	3	Member

The Committee will meet periodically to discuss child welfare measures and ways & means to promote in-country adoption of children. The tenure of such committee will be three years.

- (vi) The State Government should also set up an Adoption Cell in the Directorate of Social Welfare to co-ordinate, monitor and develop the work of adoption and render secretarial & administrative assistance to the Advisory Committee on Adoption. The Adoption Cell should consist of at least one Officer and an Assistant or more based on the number of agencies licensed and recognized in the State.
- (vii) Evolve suitable criteria for licensing/suspension/termination of License of Social/Child Welfare agencies for in-country adoption.
- (viii) Ensure that the provisions of the Supreme Court Judgements in the L.K. Pandey Vs. UOI case of 1984 and the Guidelines for Adoption issued by Govt. of India from time to time are adhered to.
- (ix) The State Government will receive data on new arrival and death of the children from all the adoption agencies and Children's Home.
- (x) The State Government will maintain list and register of prospective adoptive parents.
- (xi) The placement of children from Nursing Homes/Hospitals is illegal and prohibited. The Supreme Court directive in this regard should be strictly enforced and action should be taken against those who violate these guidelines by the State Government concerned.

- (xii) Wherever necessary, the State Government may also prepare Home Study Reports of prospective adoptive parents by its designated officers as per Guidelines, which will be acceptable to all the adoption agencies.
- (xiii) Consider for clearance cases for relaxation of age criteria for parents wishing to adopt special needs children within the country.

2.5 Inspection of Adoption Agencies.

The State Government will periodically and at least once a year, inspect or cause to be inspected, all RIPAs and LAPAs as also their papers, documents and activities connected with the service for children, generally, in order to verify the following:-

- (i) That adoption as an activity is being pursued by the organization as a welfare measure in the interest of children and not as a commercial activity.
- (ii) That proper records are being maintained for children admitted to the homes.
- (iii) That the children admitted are provided with quality child care and basic minimum facilities for their care, education and development in the institution.
- (iv) That the lists of persons interested in adopting a child or taking a child under guardianship are being maintained by the organisation regularly.
- (v) That the accounts of the organisation are being maintained and audited annually without delay and that the auditor's reports confirm that the accounts are fair and accurate; that any organisation which is in receipt of foreign funding is duly registered with the Ministry of Home Affairs and has otherwise complied with the provisions of the Foreign Contributions (Regulations) Act, 1976.
- (vi) That the organisation is receiving regular progress reports about the well-being of children given in adoption.
- (vii) That qualified staff are employed by the Agency to supervise the care of children.
- (viii) That in the case of children placed in pre-adoption foster care with the prospective adoptive parent(s), the cases have been legalized within 6 months of such placement.
- (ix) That a Central Register of prospective adoptive parent(s) is maintained.

- (x) A separate register is kept for children given in preadoption foster care in all cases.

2.6 Monitoring of Performance

The State Government will call for information and data every quarter from all RIPAs/LAPAs engaged in adoption in order to monitor the functioning of these agencies. The data will be called for in a Proforma to be prescribed by the Central Adoption Resource Authority. An annual report and audited statement of accounts will be received from all Licensed Adoption Placement Agencies.

2.7 Suspension/termination of recognition/license of RIPA/LAPA

In case of a report of malpractice by a LAPA/RIPA, the State Governments shall inform CARA and take appropriate action. It will make a suitable rehabilitation plan for the children affected by any action taken against defaulting Agencies. Normally such children should be transferred to other Agencies. The State Governments should ensure that no organization either RIPA or LAPA, indulge in any illegal activity or practice which is both against the law and not in the interest of the child. It is therefore, essential that the State Governments exercise full caution & vigilance in monitoring the activities of the adoption agencies in their respective states.

Glossary of Terms

Adoption: Adoption is a way of forming a family, involving the placement of a child with adoptive parents, followed by a legal process, which establishes a child as if he or she were born to those adoptive parents

In-Country Adoption: Adoption of an Indian child by Indian parent(s) residing in India.

Inter-country Adoption: Legal placement of an Indian child with foreign adoptive parents, PIOs (Persons of Indian Origin) and NRIs (Non Resident Indian).

H.A.M.A.	-	Hindu Adoption and Maintenance Act-1956.
G.A.W.A.	-	Guardian and Wards Act-1890.
JJ Act-2000	-	Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act-2000.

Central Adoption Resource Authority (CARA): An autonomous body functioning under Ministry of Social Justice & Empowerment to act as a Central Authority in the matter of adoptions.

Recognized Indian Placement Agency for Inter-country Adoption (RIPA): An Indian Social/Child Welfare Agency recognized by CARA for placement of Indian Children in Inter Country Adoption.

Licensed Adoption Placement Agency for In-Country Adoption (LAPA): An Indian Social/Child Welfare Agency licensed/recognized by the State Government for In-country Adoption.

Adoption Coordinating Agency (ACA): The ACA will be an organisation recognised by CARA and registered under the Registration of Societies Act and will have as its members various Adoption Agencies working in its area of jurisdiction. Its main objective is promotion of In-country adoption.

Adoption Scrutinising Agency (ASA): An independent social/child welfare agency appointed by the Court for scrutinizing adoption applications for In-country and Inter-country Adoptions.

Child Welfare Committee (CWC): A Committee as defined in JJ Act-2000 to deal with children in need of care & protection.

JJB: Juvenile Justice Board as constituted under Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act, 2000

Child Study Report (CSR): It will contain details about the child, its date of birth, social background etc.

Home Study Report (HSR): It contains details of the Adoptive Couple's social status & family background; description of Home; standard of living; relationship with spouse and family members; health details; economic status etc.

Physical Examination Report (PER): It will contain medical report of the child, report of hospitalization if any etc.

PAP: Prospective Adoptive Parents.